भारतीय
वैश्विक
परिषद्

थिंक टैंक हाउस पेपर

छोटे खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति

संयुक्त अरब अमीरात का एक मामला अध्ययन

डॉ. लक्ष्मी प्रिया

संयुक्त अरब अमीरात अरब दुनिया का केंद्र नहीं है; यह दुनिया का अरब केंद्र है ...

- मोही-दीन बिनहेंदी
नागरिक उड्डयन दुबई
के
पूर्व महानिदेशक

भारतीय
वैश्विक
परिषद

छोटे खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति

संयुक्त अरब अमीरात का एक मामला अध्ययन

डॉ. लक्ष्मी प्रिया

भारतीय
वैश्विक
परिषद

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ.एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक सरणी आयोजित करता है और प्रकाशनों का आयोजन करती है। इसमें एक सुभंडारित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह पत्रिका इंडिया क्वार्टरली प्रकाशित करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा दिया जा सके और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी है।

छोटे खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति:
संयुक्त अरब अमीरात का एक मामला अध्ययन

संयुक्त अरब अमीरात का एक मामला अध्ययन, प्रथम प्रकाशित, अक्तूबर, 2022

© भारतीय वैश्विक परिषद आईएसबीएन: 978-93-83445-67-7

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। प्रकाशक की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों का उत्तरदायित्व विशेष रूप से लेखकों के पास है और उनकी व्याख्या आवश्यक रूप से भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड

नई दिल्ली 110001, भारत,

टेलीफोन: +91-11-2331 7242 | फैक्स: +91-11-2332 2710 www.icwa.in

विषय-वस्तु

सारांश	**7**
प्रस्तावना	**9**
भाग I: संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के निर्धारक	**13**
भाग II: संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति का विकास	**43**
भाग III: संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति की बदलती गतिशीलता	**57**
निष्कर्ष	**71**
पाद-टिप्पयणियाँ	**79**

सारांश

संयुक्त अरब अमीरात एक छोटा और अपेक्षाकृत नवगठित राष्ट्र है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय और विदेश नीति की गतिशीलता इसे मध्य पूर्व में एक प्रतिष्ठित नायक बनाती है। यह शोध-पत्र यूएई की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों के चिन्हीकरण के साथ शुरू होता है। बाद में, यह पिछले पांच दशकों में संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के विकास पर चर्चा करता है। भूगोल, सामाजिक संरचना, राजनीतिक प्रणाली, सार्वजनिक राय और नेताओं के व्यक्तित्व लक्षण कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में विदेश नीति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहरी व्यवहार को ढालने में अपार आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद, यूएई इस क्षेत्र में अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। मोहम्मद बिन जायेद के सुदृढ़ नेतृत्व में, यह अपनी विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास करता है। यूएई ने महासंघ को सुदृढ़ करने और जीसीसी में एक प्रतिष्ठित भूमिका निभाने से लेकर पड़ोस और उससे परे अपनी पहुंच का विस्तार करने तक एक लंबा सफर तय किया है।

कीवर्ड: संयुक्त अरब अमीरात, विदेश नीति, छोटे राष्ट्र

सप्रू हाउस पेपर

सारांश

प्रस्तावना

विदेश नीति प्रक्रिया में शामिल तर्कसंगतता और योजना पर जोर देते हुए जानबूझकर चयनित राष्ट्रीय हितों का एक व्यवस्थित बयान है। यह अन्य राज्यों के साथ राष्ट्र के व्यवहार को एक दिशा भी देता है, इसकी ताकत की सीमा और बाहरी वातावरण की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए। विदेश नीति लंबे समय से विद्वानों के बीच अध्ययन का विषय है, हालांकि ध्यान मुख्य रूप से बड़े, सुदृढ़ और प्रमुख राज्यों पर था। ध्यान छोटे राज्यों पर स्थानांतरित हो गया जब यह महसूस किया गया कि सीमित संसाधनों और प्रबंधन के बावजूद उन्होंने अपने हितों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। विदेश नीति को चार्ल्स पी श्लेचर3 जैसे विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है जो विदेश नीति को राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली सरकार द्वारा कार्यों के एक सेट तक सीमित करते हैं। इस संबंध में, नॉर्मन पैडलफोर्ड और जॉर्ज लिंकन4 ने टिप्पणी की है कि विदेश नीति उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा एक राष्ट्र अपने व्यापक रूप से कल्पना किए गए लक्ष्यों और हितों को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने हितों को संरक्षित करने के लिए कार्रवाई के ठोस कार्यों में परिवर्तित है।

विदेश नीति सिद्धांतों के एक समूह का निर्माण और कार्यान्वयन है जो अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा या आगे बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों के साथ समन्वय करते समय एक राष्ट्र के व्यवहार पैटर्न को आकार देता है।

विदेश नीति सिद्धांतों के एक समूह का निर्माण और कार्यान्वयन है जो अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा या आगे बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों के साथ समन्वय करते समय एक राष्ट्र के व्यवहार पैटर्न को आकार देता है5। विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य राष्ट्रीय हित के अनुसार दूसरे के व्यवहार को ढालना है। इस संदर्भ में, जॉर्ज मॉडलस्की6 विदेश नीति को अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने और अंतरराष्ट्रीय वातावरण में अपनी गतिविधियों को समायोजित करने के लिए समुदायों द्वारा विकसित गतिविधियों की प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है। महेंद्र कुमार ने जोर देकर कहा कि विदेश नीति को अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने के साथ-साथ विनियमित करने का प्रयास करना चाहिए और अन्य राज्यों के व्यवहार को परिवर्तन के साथ-साथ यथास्थिति के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है।

विदेश नीति के अध्ययनों के विकास के साथ, यह माना गया कि एक निश्चित विदेश नीति की अनुपस्थिति भी एक विदेश नीति है। ताइवान के प्रति वाशिंगटन की नीति की सामरिक अस्पष्टता बिंदु में एक मामला

है। बाहरी घटनाओं का प्रत्युत्तर देने और बाहरी नायकों के साथ जुड़ने के आधार पर, अधिकांश राज्यों की एक परिभाषित/अपरिभाषित विदेश नीति है। हालांकि, प्रत्येक राष्ट्र विशिष्ट आवश्यकताओं और हितों के आधार पर एक अलग तरीके से व्यवहार करता है। चूंकि प्रत्येक राष्ट्र को विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैचारिक उद्देश्यों का अनुसरण करना पड़ता है, इसलिए यह अपने हितों के आधार पर कई नीतियां बनाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समय बीतने के साथ हित बदल सकते हैं जो राष्ट्र द्वारा विविध नीतियों को जन्म देते हैं। हालांकि, विदेश नीति के लक्ष्य अधिक स्थिर हैं और समय के साथ विकसित होते हैं। चार्ल्स लेर्चे और अब्दुल सईद 10 'विदेश नीति' और 'विदेश नीतियों' के बीच अंतर की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि पूर्व को लक्ष्यों के संदर्भ में वाक्यांशित किया जाता है जबकि बाद में उद्देश्यों से उनकी प्रासंगिकता प्राप्त होती है। विदेश नीति की एक व्यापक परिभाषा में तीन तत्व शामिल हैं: लक्ष्य या उद्देश्य, नीति योजनाएं और अपने बाहरी संबंधों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्र द्वारा किए गए वास्तविक कार्य। विदेश नीति भूगोल, समाज, राजनीति और राष्ट्र के लिए विशिष्ट आर्थिक स्थितियों जैसे कई निर्धारकों पर आधारित है। यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर भी निर्भर करता है। छोटे राज्यों के लिए, निवारकों का बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाओं के प्रभाव को सहन करने की उनकी क्षमता सीमित है।

यह शोध संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की विदेश नीति का अध्ययन करने और हाल के परिवर्तनों का कारण बनने वाले प्रमुख निर्धारकों का पता लगाने का एक प्रयास है। इसे तीन खंडों में बांटा गया है। पहला भाग यूएई की विदेश नीति निर्धारकों पर चर्चा करता है और दूसरा भाग अपने पड़ोसियों, क्षेत्रीय नायकों और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति यूएई की विदेश नीति के विकास की जांच करता है। तीसरा भाग संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति की बदलती गतिशीलता पर केंद्रित है।

संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के निर्धारक

सप्रू
हाउस
पेपर

चित्र 1: विदेश नीति निर्धारक

क) भूगोल

भूगोल, विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आंतरिक निर्धारक है। आकार, आकार, स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, सीमाएं और पड़ोसी राष्ट्र के हितों और चिंताओं को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आकार एक आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बड़ा है जो पर्याप्त सैन्य प्रतिष्ठान को संभाल सकता है; जलवायु समान है और शारीरिक शक्ति के लिए अनुकूल है; स्थलाकृति प्राकृतिक रक्षा बाधाओं के साथ सीमाएं प्रदान करती है और आकार कॉम्पैक्ट है; राष्ट्र में एक स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने की क्षमता होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने भूगोल की भौतिक अभिव्यक्तियों को अनावश्यक छोड़ दिया है; हालांकि, भूगोल की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियों जैसे आकार और संबंधित विशेषताएं जो विदेश नीति के निर्णयों में परिलक्षित होती हैं, उनकी काफी प्रासंगिकता है। इसी तरह, इतिहास, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सैन्य क्षमता और नेतृत्व की एक राष्ट्र की विदेश नीति को आकार देने में एक सुदृढ़ भूमिका है।

यूएई दक्षिण में सऊदी अरब और पश्चिम में ओमान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और कतर के साथ 19 किमी की विवादित सीमा भी साझा करता है। मौजूदा सीमा मुद्दे छोटे खाड़ी राष्ट्र को क्षेत्र के भीतर और बाहर के देशों के साथ सुदृढ़ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक बनाते हैं। सऊदी अरब के साथ सीमा विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है; रियाद ने 1993 में 1974 की जेद्दा संधि की पुष्टि की, हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात ने अभी तक डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ओमान के साथ सीमा मुद्दा भी अनसुलझा है, बावजूद इसके कि दोनों देश मई 1999 में सीमा को रेखांकित करने पर सहमत हुए थे। तीन खाड़ी द्वीपों, अर्थात् अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब और लेसर टुम्ब पर विवाद अभी भी संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को परेशान करता है; अमीरात ने तेहरान की अनिच्छा के बावजूद इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में ले जाने का प्रयास किया। लगातार विवादों के कारण यूएई ने सुदृढ़ रक्षा नीति को आगे बढ़ाया और रक्षा उद्देश्यों के लिए अपने संघीय बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया। यूएई हथियारों के चौथे सबसे बड़े आयातक के रूप में दिखाई देता है और 2011-2015 के दौरान कुल आयात का 4.6 प्रतिशत योगदान देता है।

मौजूदा सीमा मुद्दे छोटे खाड़ी राष्ट्र को क्षेत्र के भीतर
और बाहर के देशों के साथ सुदृढ़ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों
को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक बनाते हैं।

चित्र 2: संयुक्त अरब अमीरात का नक्शा

स्रोत: यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, http://countrystudies.us/persian-gulf-states/81.htm

संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब के साथ एक बड़ी सीमा साझा करता है, जो एक क्षेत्रीय दिग्गज है और परिणामस्वरूप एक अर्ध-स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। फिर भी इसने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जब भी यह सऊदी दबाव को संतुलित करने में सक्षम था या जब इसके राष्ट्रीय हित खतरे में थे। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब की तुलना में 1979 की ईरानी क्रांति के प्रति अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी विदेश नीति को सऊदी अरब के साथ कभी-कभी संरेखित किया जैसा कि 1976 के दोहा ओपेक सम्मेलन में तेल की कीमतों पर यूएई-सऊदी रुख में स्पष्ट है। ईरान के संबंध में, संयुक्त अरब अमीरात की नीति हमेशा इस तथ्य पर विचार करती रही है कि अमीराती तेल क्षेत्र ईरानी हवाई हमलों के लिए खुले हैं, संयुक्त अरब अमीरात में एक बड़ा ईरानी समुदाय है जो एक महत्वपूर्ण शिया अल्पसंख्यक बना रहा है और इसका ईरान के साथ पुन: निर्यात व्यापार है।

सीमा विवादों ने संयुक्त अरब अमीरात-ओमान संबंधों पर सुदृढ़ छाप छोड़ी है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना 1999 में ओमान के साथ सीमा सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर करने पर हुई थी। इसके अलावा, दोनों देशों ने 2005 में सीमा सीमांकन के एक विस्तृत नक्शे पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात में फारस की खड़ी में 650 किमी और ओमान की खड़ी में 90 किमी की लंबी तटरेखा है। लंबी तटरेखा ओर होर्मुज जलडमरूमध्य तक पहुंच संयुक्त अरब अमीरात को एक सामरिक लाभ प्रदान करती है, जबकि इसे कई चुनौतियों के लिए भी खोलती है। 2019 में तेल टैंकरों पर कथित ईरानी हमलों के बाद, यह स्पष्ट है कि एक स्थिर फारस की खड़ी के साथ-साथ ओमान की खाड़ी संयुक्त अरब अमीरात की समृद्धि के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। अमीरात सऊदी अरब, बहरीन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन में शामिल हो गया, जिसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में और उसके पास अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की रक्षा करना है।

सऊदी अरब और ईरान के साथ सीमा साझा करते हुए, जिनके

पास 18 गुना बड़े क्षेत्र हैं, यूएई खुद को फारस की खाड़ी में एक छोटे राष्ट्र के रूप में मानता है।

निकोलस स्पाइकमैन ने 1938 में प्रकाशित अपने लेख में उल्लेख किया कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति पर क्षेत्रीय स्थान के प्रभाव को समझने के लिए परिवेश की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।अमीरात का पांच दशकों का छोटा इतिहास इंगित करता है कि संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका करीबी साझेदार रहे हैं। दोनों देशों ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और अमेरिका यूएई को निर्यात और सीमा सुरक्षा (ईएक्सबीएस) सहायता प्रदान करता है। यह इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, और 1,000 से अधिक अमेरिकी कंपनियां देश में काम करती हैं। अमेरिका के साथ यूएई के सुदृढ़ संबंधों ने इसे क्षेत्र में एक सक्रिय और मुखर विदेश नीति को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित और सशस्त्र एक सैन्य ने संयुक्त अरब अमीरात को इस्लामी संगठनों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय और घरेलू खतरों का मुकाबला करने में मदद की है।

प्रवासियों की उपस्थिति जो 88 प्रतिशत आबादी के रूप में बनती है, संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू और विदेश नीति के गठन का एक प्रमुख निर्धारक है।

यूएई ने सऊदी अरब, मिस्र और बहरीन के साथ मिलकर 2017 में शासन में इस्लामवादियों की भूमिका और अन्य मुद्दों पर कतर का बहिष्कार किया था। सऊदी अरब और ईरान के साथ सीमा साझा करते हुए, जिनके पास 18 गुना बड़े क्षेत्र हैं, यूएई खुद को फारस की खाड़ी में एक छोटे राष्ट्र के रूप में मानता है। सऊदी अरब विभिन्न मुद्दों पर इसे अपने साझेदार राष्ट्र के रूप में देखता है, जबकि ईरान इसे एक आसान पड़ोसी के रूप में देखता है। उसका मानना है कि सलमान गैस क्षेत्रों के साझा कब्जे को देखते हुए सऊदी अरब की तुलना में यूएई को आसानी से पकड़ा जा सकता है। फारस की खाड़ी के अन्य पड़ोसी देश अमीरात को एक सुदृढ़ आर्थिक क्षमता रखने वाले क्षेत्र के मामले में एक छोटे राष्ट्र के रूप में देखते हैं। पिछले दो दशकों में, यूएई ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी छवि और कद को फिर से परिभाषित किया। पर्याप्त हाइड्रोकार्बन संसाधनों की उपस्थिति ने यूएई को ताकत और कद प्रदान किया जो क्षेत्र के संदर्भ में इसकी कमी थी।

ख) समाज और जनसांख्यिकी

विदेश नीति के निर्माण में सामाजिक स्थिति और जनसांख्यिकीय संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त अरब अमीरात की आबादी 10 मिलियन के करीब है, जिसमें से केवल 12 प्रतिशत मूल निवासियों द्वारा गठित है। इस प्रकार, प्रवासियों की उपस्थिति जो 88 प्रतिशत आबादी के बराबर है, संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू और विदेश नीति के गठन का एक प्रमुख निर्धारक है। संयुक्त अरब अमीरात ने 1973 के संघीय कानून संख्या 6 के माध्यम से आप्रवासन और प्रवासियों के निवास से संबंधित कानूनों को अपनाया और संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार से संबंधित सभी मामलों को 1980 के संघीय कानून संख्या 8 द्वारा शासित किया जाता है। इसने प्रवासी आबादी के लिए रोजगार, सुरक्षा और काम के माहौल पर कानून भी बनाए हैं।

इसने बदलते परिदृश्यों और आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए समय-समय पर इन कानूनों में संशोधन भी किया है; उदाहरण के लिए, मानव तस्करी अपराधों का मुकाबला करने से निपटने के लिए 2006 के संघीय कानून संख्या 51 को 2015 में संशोधित किया गया था। मूल कानून में धोखे या बल के माध्यम से मनुष्यों की तस्करी करने वाले व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान था, जबकि संशोधित संस्करण अधिक व्यापक है और इसमें वे लोग शामिल हैं जो कमजोर लोगों को शोषणकारी श्रम स्थितियों में हेरफेर करने के लिए निर्वासन के खतरों का उपयोग करते हैं। यूएई ने कृषि, सार्वजनिक सेवाओं और घरेलू कार्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के लिए अलग कानून भी तैयार किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात लगभग 750,000 घरेलू श्रमिकों की मेजबानी करता है और तदनुसार भर्ती, मजदूरी के भुगतान, छुट्टी और मुआवजे, व्यावसायिक सुरक्षा और विवाद समाधान (2017 के संघीय डिक्री नंबर 10) के लिए नीतियां तैयार की हैं।

संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और अन्य अरब देशों से आने वाले प्रवासियों को गैर-अरब देशों से आने वाले प्रवासियों पर प्राथमिकता देता है और यह श्रम कानूनों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जीसीसी नागरिकों के लिए मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव हैं; 2005 का मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 1215 निजी क्षेत्र में काम करने वाले जीसीसी नागरिकों को पंजीकृत करने से संबंधित है, 2007 का मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 4 जीसीसी नागरिकों को देश में आर्थिक गतिविधियों और व्यवसायों का अभ्यास करने की अनुमति देने से संबंधित है, और 2015 का मंत्रिस्तरीय आदेश संख्या 292 जीसीसी राष्ट्रीय कर्मचारियों के रोजगार की स्थितियों को नियंत्रित करता है। इसी तरह, यूएई में काम करने के लिए आने वाले अरब नागरिकों के बारे में विशेष कानून हैं; 2009 का कानून 24 संयुक्त अरब अमीरात में सीरियाई श्रमिकों की भर्ती के लिए समझौते की पुष्टि करता है, 2007 का संघीय डिक्री नंबर 92 यूएई और जॉर्डन के बीच जनशक्ति सहयोग की पुष्टि करता है, और 2005 का राष्ट्रपति डिक्री नंबर 215 संयुक्त अरब अमीरात और यमन के बीच श्रम सहयोग की पुष्टि करता है।

दूसरे, ऐसे कई समय हुए हैं जब यूएई ने प्रवासियों की एक विशाल आबादी की उपस्थिति को देखते हुए विदेश नीति के निर्णय लिए हैं। प्रवासी श्रमिकों पर भारी निर्भरता ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेशी संबंधों को एक से अधिक बार जटिल बना दिया है। भारत ने 1981 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

(आईएलओ) सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। उसके बाद, इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विदेशी श्रमिकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। अमीरात ने इन दावों का खंडन किया और आधिकारिक तौर पर अरब उत्तरी अफ्रीकी देशों से आईएलओ में प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को लाने से रोकने के लिए कहा। इसके अलावा, अमीराती नागरिकों के विशाल बहुमत ने खुले दरवाजे की आव्रजन नीति पर नाराजगी व्यक्त की, जो यूएई को गैर-अरब श्रम पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर करती है। संयुक्त अरब अमीरात का उद्देश्य ट्यूनीशिया, मोरक्को और सूडान जैसे अफ्रीकी देशों के साथ कई श्रम समझौतों पर हस्ताक्षर करके अरब प्रवासियों द्वारा गैर-अरब श्रम को बदलना है। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब देशों में श्रम अटैचियों को भी नियुक्त किया। हालांकि, उपाय स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुए; यूएई ने 1989 में 82 प्रतिशत प्रवासी मजदूरों की मेजबानी की और तीन दशकों से अधिक समय के बाद, 2022 में कुल आबादी का 88 प्रतिशत हिस्सा प्रवासी हैं।

गैर-राष्ट्रीय जनसांख्यिकी प्रेषक देशों की तुलना में संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति को प्रभावित करती है। यूएई और फिलीपींस ने 2021 में घरेलू कामगारों की भर्ती पर प्रतिबंध हटा दिया था। दोनों देशों ने फिलिपिनो घरेलू श्रमिकों को दुरुपयोग से बचाने और उचित मजदूरी और उपयुक्त कामकाजी परिस्थितियों के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिलीपींस से नौकरानियों की कानूनी भर्ती 2014 में बंद हो गई, जब देश ने अपने नागरिकों को लापरवाही के मामलों के परिणामस्वरूप संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू श्रमिकों के रूप में नौकरी करने से रोक दिया। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) ने घरेलू श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करने और श्रमिकों के लिए उचित वीजा, अभिविन्यास और प्रशिक्षण की गारंटी के लिए एकल केंद्र बनाने के लिए ताड़बीर केंद्र खोलने की घोषणा की। एमओएचआरई में मानव संसाधन मामलों के अवर सचिव सैफ अहमद अल सुवैदी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने श्रम-निर्यातक सरकारों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए मंत्रालय की योजना के हिस्से के रूप में भारत, श्रीलंका और केन्या सहित कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संविदात्मक रोजगार के सभी चरणों के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए श्रम-निर्यातक देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के अलावा।

जैसा कि यूएई अपनी विदेश नीतियों को विभिन्न दिशाओं में
ढालता है, लोकप्रिय दृष्टिकोण मोटे तौर पर इन निर्णयों के साथ
तालमेल में हैं।

संयुक्त अरब अमीरात पर घरेलू कामगारों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और उसने स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त और समय पर उपाय किए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच

(एचआरडब्ल्यू) ने *कफाला* या प्रायोजन प्रणाली के भयावह परिणामों का दस्तावेजीकरण करते हुए 79 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कैसे संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू श्रमिक नियोक्ता की सहमति के बिना अपने अनुबंध समाप्त होने से पहले नई नौकरी में नहीं जा सकते हैं, जिससे कई लोग अपमानजनक परिस्थितियों में फंस जाते हैं। *कफाला* प्रणाली प्रवासी श्रमिकों को व्यक्तिगत नियोक्ताओं से जोड़ती है जो उनके वीजा प्रायोजकों के रूप में कार्य करते हैं, और नियोक्ताओं को बदलने के लिए प्रवासी श्रमिकों की क्षमताओं को प्रतिबंधित करते हैं। यह प्रणाली नियोक्ताओं को कर्मचारियों पर बड़ी शक्ति देती है क्योंकि यह उन्हें किसी भी समय प्रायोजन को रद्द करने का अधिकार देती है। 2015 में, अमीराती श्रम मंत्री, साकर घोबाश ने *कफाला* प्रणाली में सुधार करने और विदेशी श्रमिकों को अपने अनुबंध को समाप्त करने और नियोक्ता बदलने की अनुमति देने के उपायों की घोषणा की।

तीसरा, जनता की राय का यूएई की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। ईरान को नाराज करने के लिए तैयार नहीं होने के बावजूद, जिसके साथ अबू धाबी और दुबई के घनिष्ठ संबंध थे, यूएई संघीय सरकार ने ईरान-इराक युद्ध के दौरान इराक का समर्थन किया। संयुक्त अरब अमीरात अरब जनता की राय से अछूता नहीं था, जिसके अनुसार द्वीप मुद्दे पर उदासीनता को देशभक्ति की कमी माना जाता था। दुबई में वोलोंगोंग विश्वविद्यालय द्वारा एक पायलट अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि संयुक्त अरब अमीरात में जनता यूएई की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर सुदृढ़ जोर देती है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी पोल द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन ने अब्राहम समझौते पर आबादी के बढ़ते समर्थन और इजरायल के साथ खेल और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने का दस्तावेजीकरण किया।

जैसा कि यूएई अपनी विदेश नीतियों को विभिन्न दिशाओं में ढालता है, लोकप्रिय दृष्टिकोण मोटे तौर पर इन निर्णयों के साथ तालमेल में हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार, 2017 में चारों द्वारा कतर को अलग-थलग करने के बाद, 46 प्रतिशत अमीरातियों ने सहमति व्यक्त की कि जीसीसी और अरब देशों को कतर का बहिष्कार करना चाहिए जब तक कि वह उनकी मांग को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि, कतर के साथ अल-उला घोषणा पर हस्ताक्षर करने से एक वर्ष पहले, 59 प्रतिशत अमीरातियों ने सहमति व्यक्त की कि एक समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों के लिए समझौता करना है। संयुक्त अरब अमीरात के लिए अमेरिका और अन्य बाहरी नायकों के महत्व के प्रश्न पर, 50 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की कि यूएई अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता है और इस प्रकार भागीदारों के रूप में चीन या रूस की ओर अधिक देखना चाहिए। इसके अलावा, सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब्राहम एकॉर्ड्स की लोकप्रियता जून 2020 में 44 प्रतिशत समर्थन से घटकर दिसंबर 2020 में 23 प्रतिशत हो गई। यूएई में फिलिस्तीन समर्थक भावना लंबे समय से सुदृढ़ रही है और अमीराती निर्वासित समुदायों में भी परिलक्षित हुई, जिनमें से कुछ इस्लामी समूह अल-इस्लाह के सदस्य थे. अमीराती कार्यकर्ता सामान्यीकरण समझौते को संयुक्त अरब अमीरात के भविष्य के लिए एक झटके के रूप में देखते हैं और इसे इजरायली एजेंटों द्वारा राष्ट्र की घुसपैठ और भविष्य के दमन के लिए संभावित कवर के रूप में चित्रित करते हैं। इसके अलावा, अगस्त-सितंबर 2018 में ज़ोग्बी रिसर्च सर्विसेज द्वारा आयोजित मध्य पूर्व जनमत के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में असद विरोधी विचारों में काफी नरमी आई; दिलचस्प बात यह है कि

यूएई ने दिसंबर 2018 में सीरिया में अपना दूतावास फिर से खोल दिया।

संयुक्त अरब अमीरात में विदेश नीति निर्णय लेने में संघीय संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूएई का संविधान संघ को बहुमत विदेश नीति निर्माण शक्तियां प्रदान करता है (अनुच्छेद 120-121) जबकि संबंधित अमीरात को बाकी विषयों (अनुच्छेद 122-123) पर विधायी शक्ति प्रदान करता है।

ग) राजनीति

किसी देश की विदेश नीति बनाने में राजनीतिक प्रणाली की भी प्रमुख भूमिका होती है। सात अमीरात के संघ के रूप में गठित होने से पहले, संयुक्त अरब अमीरात एक ब्रिटिश संरक्षक था और यह एक हद तक यूएई की पश्चिम-उन्मुख विदेश नीति की व्याख्या करता है। संयुक्त अरब अमीरात में विदेश नीति निर्णय लेने में संघीय संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त अरब अमीरात का संविधान संघ को बहुमत विदेश नीति निर्माण शक्तियां प्रदान करता है (अनुच्छेद 120-121) जबकि संबंधित अमीरात को बाकी विषयों (अनुच्छेद 122-123) पर विधायी शक्ति प्रदान करता है। यह संघ को विदेश नीति के निर्णयों को लागू करने का उत्तरदायित्व भी प्रदान करता है (अनुच्छेद 125)। संयुक्त अरब अमीरात के संविधान के अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि विदेशी मामले, रक्षा और सुरक्षा, आव्रजन, श्रम संबंध और क्षेत्रीय जल संघीय मामले हैं।

अनुच्छेद 122 में उल्लेख किया गया है कि अलग-अलग अमीरात के पास उन सभी मामलों में अधिकार क्षेत्र होगा जो विशेष रूप से संघीय अधिकारियों को प्रदान नहीं किए गए हैं। अनुच्छेद 123 में प्रावधान है कि संयुक्त अरब अमीरात का एक सदस्य अमीरात पड़ोसी देशों के साथ स्थानीय और प्रशासनिक प्रकृति के सीमित सम्मेलनों का समापन कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे सम्मेलन यूएई या संघीय कानूनों के हितों के साथ संघर्ष में न हों। अनुच्छेद 124 व्यक्तिगत अमीरात के साथ पूर्व परामर्श प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 125 अमीरात को संघीय कानूनों और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को लागू करने का आदेश देता है।

दूसरे, जैसा कि यूएई किसी भी संगठित राजनीतिक दलों या समूहों के बिना सात अमीरात का एक संघ है, व्यक्तिगत अमीरात का कम से कम शुरुआती दशकों में विदेश नीति निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ा जब वे एक अनंतिम संविधान द्वारा शासित थे। इसके गठन के बाद पहले दो दशकों में कुछ अंतर-अमीरात मुद्दों में फुजैराह-शारजाह क्षेत्रीय विवाद 22 आदिवासियों की हत्या पर, रास अल खैमाह-शारजाह घाटी में फॉस्फेट जमा पर विवाद, अबू मूसा के अपतटीय तेल जमा पर अजमान-शारजाह-उम अल कुवैन विवाद और फुजैरा

और रास अल-खैमा के बीच आदिवासी संघर्ष शामिल थे।

संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक पिता, शेख जायेद बिन सुल्तान अल-नाहयान, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के अग्रणी भी थे।

अंतर-अमीरात प्रतिद्वंद्विता और समाज की आदिवासी प्रकृति का विदेश नीति पर असर पड़ा क्योंकि व्यक्तिगत अमीरात आंतरिक संघर्षों को हल करने के लिए पड़ोसी देशों को आमंत्रित करने वाले मुद्दों से निपटते थे। संयुक्त अरब अमीरात की साप्ताहिक पत्रिका अल-आज़मीना अल-अरबिया के अनुसार, शारजाह के शेख सुल्तान ने ओमान के सुल्तान कबूस से दुबई-शारजाह मुद्दे को सुलझाने के लिए संपर्क किया। अबू धाबी और दुबई के बीच 1979 के राजनीतिक संकट और आर्थिक स्वायत्तता के साथ ढीले संघ ने संयुक्त अरब अमीरात को संकट को समाप्त करने के लिए सऊदी समर्थन मांगने के लिए प्रेरित किया, जबकि कुवैत के विदेश मंत्री ने शटल कूटनीति में दोनों के बीच मध्यस्थता करने में कई दिन बिताए।

ऐसे समय भी थे जब अबू धाबी और दुबई के प्रभुत्व वाले यूएई ने विदेश नीति के फैसले किए जो अन्य अमीरात के विचारों के अनुरूप नहीं थे; उदाहरण के लिए, 1971 में रास अल-खैमा ने मांग की कि संयुक्त अरब अमीरात को सशस्त्र बलों के उपयोग से ईरान से तीन द्वीपों को ले लेना चाहिए लेकिन संघीय सरकार ने केवल खाड़ी द्वीपों पर ईरानी कब्जे की निंदा की; यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अबू धाबी, दुबई और शारजाह के तेहरान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इसी तरह, 1980 के ईरान-इराक युद्ध के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात ने तर्कसंगत समाधान की आशा करते हुए इराक का समर्थन किया, जबकि रास अल-खैमा शासक ने बगदाद का दौरा किया। अरब देश के साथ एकजुटता की उनकी अभिव्यक्ति को संघीय सरकार द्वारा सराहा नहीं गया था।

2004 में शेख जायेद बिन नाहयान के निधन और 2011 में पूरे क्षेत्र को घेरने वाले अरब स्प्रिंग के बाद अमीराती विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया।

तीसरा, व्यक्तिगत नेताओं और उनके व्यक्तित्वों की भूमिका का भी संयुक्त अरब अमीरात में विदेश नीति के गठन पर प्रभाव पड़ा। नेताओं ने दुनिया भर में विदेश नीति के पाठ्यक्रम को आकार देने या बदलने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एडॉल्फ हिटलर, वुडरो विल्सन और विंस्टन चर्चिल से लेकर जैक्स शिराक, व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मर्केल, मार्गरेट थैचर, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा को आकार दिया है। क्षेत्र के भीतर सद्दाम हुसैन, गमाल अब्देल नासिर, हाफिज अल-असद, फैसल बिन अब्दुलअजीज अल-सऊद, रुहोल्लाह खोमैनी, मुअम्मर अल-गद्दाफी और सुल्तान कबूस बिन सईद ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विदेश नीति के गठन पर अपनी छाप छोड़ी है। इसी तरह, पांच दशकों के एक छोटे से इतिहास में, यूएई में ऐसे नेता रहे हैं जिनके व्यक्तित्व और करिश्मे ने यूएई की विदेश नीति को ढाला है।

संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक पिता, शेख जायेद बिन सुल्तान अल-नाहयान, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के अग्रणी भी थे। उन्होंने अरब एकता की वकालत की और फिलिस्तीन के कारण का समर्थन किया। संयुक्त अरब अमीरात ने 1973 के अरब तेल प्रतिबंध में भाग लिया, और अरब-इजरायल संघर्ष में अग्रिम पंक्ति के राज्यों को व्यापक समर्थन प्रदान किया। 35 वर्ष 1980 और 1990 के दशक में, उनके नेतृत्व में, संयुक्त अरब अमीरात ने एक मध्यमार्गी नीति का पालन किया, जिसमें क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थता को अपने केंद्र में रखा गया। वर्ष 1990 के दशक के अंत में, क्राउन प्रिंस खलीफा बिन जायेद अल-नाहयान के नेतृत्व में यूएई की विदेश नीति अरब और इस्लामी मुद्दों से दूर चली गई, जिन्होंने अपने पिता के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण केंद्र मंच हासिल किया। संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति वैश्विक विकास और अंतरराष्ट्रीय शासन की ओर बढ़ी, जिसका उद्देश्य 'नरम' और 'कठोर' शक्ति का भंडार इकट्ठा करना था। 9/11 के बाद, संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को गहरा करना शुरू कर दिया और 2001-2014 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी लड़ाकू बलों का समर्थन करते हुए अपने बलों को तैनात किया। उनकी विदेश नीति की एक और विशेषता यह थी कि यूएई अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी गारंटी पर निर्भर था। यह 1981 में जीसीसी का हिस्सा बन गया और कुवैत पर इराक के आक्रमण के बाद इसे कुवैत जैसे जीसीसी सदस्य राज्यों की रक्षा करने में सऊदी अरब की अक्षमता का एहसास हुआ। कुवैत के आक्रमण ने संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा के लिए बाहरी नायकों को देखने के लिए मजबूर किया।

2004 में शेख जायेद बिन नाहयान के निधन के बाद अमीराती विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया; और अरब स्प्रिंग जिसने 2011 में पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हालांकि 2004-2022 से यूएई पर खलीफा बिन जायेद बिन नाहयान का शासन था, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान, जो 2014 में अपने बड़े भाई और यूएई के राष्ट्रपति को कमजोर स्ट्रोक का सामना करने के बाद वास्तविक नेता बन गए, को संयुक्त अरब अमीरात के एक क्षेत्रीय नायक के रूप में उभरने का श्रेय दिया जाता है, जो अपने भू-राजनीतिक वजन से ऊपर उठकर अपने स्वयं के हित को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यवस्था को नया आकार देने के लिए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर खुद को सुदृढ़ करने का श्रेय देता है। बिन जायेद के राजनीतिक कौशल ने उन्हें अमीराती निर्णय लेने की प्रक्रिया पर काफी प्रभाव डालने में सक्षम बनाया और वर्तमान में यूएई की विदेश नीति उनके व्यक्तित्व और विश्वदृष्टि का प्रत्यक्ष उत्पाद है।

मोहम्मद बिन जायेद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के हॉब्सियन दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और राजनीतिक मतभेदों को

हल करने के लिए एक उपकरण के रूप में सेना की दक्षता में विश्वास करते हैं; उन्होंने अमीराती सशस्त्र बलों के समेकन का संचालन किया और इसका उद्देश्य एक कुशल स्वदेशी रक्षा उद्योग स्थापित करना है। वह एक महत्वाकांक्षी शासक है, जो अपने देश को "अंतरराष्ट्रीय पहुंच के साथ क्षेत्रीय शक्ति" बनाने के लिए तरसता है। वह संयुक्त अरब अमीरात को पश्चिमी हिंद महासागर की दुनिया में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्रमुख वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र में बदलने का इरादा रखता है। वह दुबई के आर्थिक उदारवाद और अबू धाबी द्वारा लागू धर्मनिरपेक्ष अति-अधिनायकवाद के आधार पर मध्य पूर्व की क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को नया रूप देने का भी इरादा रखता है।

यूएई 2021 में लगभग 2.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी
वृद्धि दर के साथ तीसरी सबसे बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है।
इसके पास दुनिया के तेल भंडार का 6 प्रतिशत और सातवां
सबसे बड़ा सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार है जो निकट भविष्य में
यूएई की अर्थव्यवस्था का आधार बना रहेगा।

घ) अर्थव्यवस्था

आर्थिक परिवर्तन और सुधार विदेश नीति का एक और निर्धारक हैं; उदारीकरण एक महत्वपूर्ण विकास था जिसने भारत सहित कई देशों की विदेश नीति के मौजूदा पाठ्यक्रम को बदल दिया। आर्थिक कूटनीति राजनीतिक कूटनीति की जगह लेने वाले देशों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गई है और भू-आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तकनीकी क्रांति, बढ़ती अन्योन्याश्रितता, वैचारिक लड़ाइयों के लिए मोहभंग ने देशों को राजनीतिक कूटनीति के बजाय आर्थिक कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। देश राजनीतिक टकराव, शत्रुता और मतभेदों को आर्थिक सहयोग और संवाद के साथ बदलना पसंद करते हैं। किसी देश के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ नीतिगत साधनों में व्यापार, सब्सिडी, निर्यात-आयात कोटा, स्वैच्छिक निर्यात आरक्षण और आयात विस्तार आदि शामिल हैं। आर्थिक नीति की सफलता आर्थिक परिसंपत्तियों और क्षमताओं में निहित है और एक सुदृढ़ आर्थिक नीति के लिए एक पूर्व-आवश्यकता एक अच्छी आर्थिक घरेलू व्यवस्था है। आर्थिक कूटनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए बिना वैश्विक गठजोड़ सुनिश्चित करना है।

यूएई 2021 में लगभग 2.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के साथ तीसरी सबसे बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। इसके पास दुनिया के तेल भंडार का 6 प्रतिशत और सातवां सबसे बड़ा सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार है जो निकट भविष्य में यूएई की अर्थव्यवस्था का आधार बना रहेगा। हालांकि, इसने आर्थिक विविधीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70 प्रतिशत अब

गैर-तेल क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न होता है। 2021 में राष्ट्रीयता के 50 वर्ष का उत्सव मनाते हुए, संयुक्त अरब अमीरात ने देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और अगले नौ वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में अमरीकी डॉलर 150 बिलियन को आकर्षित करने के लिए 50 नई आर्थिक पहल शुरू की।

सितंबर 2021 में अनावरण की गई पहली 13 पहलों में यूएई को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाने की क्षमता है। अत्यधिक कुशल व्यवसायियों, निवेशकों, उद्यमियों और छात्रों के लिए ग्रीन वीजा का प्रावधान; और फ्रीलांसर वीजा, स्व-नियोजित श्रमिकों के लिए पहला संघीय वीजा खाड़ी देश में प्रतिभा को आकर्षित करेगा। इसी तरह 10x10 कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा एक स्मार्ट कदम है और इसका उद्देश्य चीन, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इटली, रूस, पोलैंड, लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया सहित 10 वैश्विक बाजारों में यूएई निर्यात में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करना है।

संयुक्त अरब अमीरात चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और अरब क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का समर्थन करता है और सहयोग माल की आवाजाही से परे जाने की आशा है।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के महत्व से अवगत, संयुक्त अरब अमीरात 1967 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) में शामिल हो गया और 1973 में तेल प्रतिबंध के दौरान पूर्ण समर्थन प्रदान किया। यह गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों के महत्व से भी अवगत है; ओपेक सदस्यों के साथ, वे वैश्विक तेल आपूर्ति का 55 प्रतिशत और दुनिया के सिद्ध तेल भंडार का 90 प्रतिशत मालिक हैं। मार्च 2022 में, संयुक्त अरब अमीरात ने जोर देकर कहा कि यह ओपेक+समझौते और इसके मासिक तेल उत्पादन तंत्र के लिए खुला है। जब सऊदी अरब ने ओपेक में अगस्त से दिसंबर 2021 तक लगभग 2 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन बढ़ाने और 2022 के अंत तक शेष कटौती का विस्तार करने के लिए दबाव डाला, तो यूएई ने कहा कि अप्रैल 2022 की प्रारंभिक समय सीमा से परे उत्पादन में कटौती अनुचित होगी; दोनों देश जुलाई 2021 में एक समझौता समझौते पर पहुंचे। सदस्यों, अबू धाबी में अपने तेल और गैस क्षेत्रों में इक्विटी निवेशकों के रूप में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ब्रिटिश तेल और गैस कंपनी बीपी पीएलसी और फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज एसई जैसे लंबे समय से साझेदार, 2010 के दशक के अंत में भारत और चीन की कंपनियों से जुड़ गए हैं।

दूसरे, विदेशी निवेश में विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में कोविड-19 के बावजूद विदेशी निवेश में वृद्धि देखी है और अमीरात में एफडीआई ने 2020 की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान 4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। देश ने अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ निवेश की रक्षा और प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 106 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब, कुवैत और नीदरलैंड संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेश भागीदार हैं और खाड़ी देश के स्पष्ट रूप से उन सभी के साथ अच्छे संबंध हैं।

संयुक्त अरब अमीरात चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और अरब क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का समर्थन करता है और सहयोग माल की आवाजाही से परे जाने की आशा है। यूएई बीआरआई के डिजिटल पहलुओं और चीन के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों से लाभ उठाना चाहता है। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि यूएई अमीरात में निवेश करने वाले देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लाभों से अवगत है, यह अन्य देशों में निवेश के माध्यम से साझेदारी बढ़ाने के फलों से भी अच्छी तरह से परिचित है। यूएई वैश्विक आर्थिक भागीदारी के तहत आठ सामरिक वैश्विक बाजारों के साथ व्यापक आर्थिक समझौते कर रहा है, जिसका उद्देश्य इन बाजारों के साथ वर्तमान डीएच 257 बिलियन व्यापार मात्रा में 40 बिलियन वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक समझौतों के लिए एक उच्चतर समिति की भी स्थापना की है। जीसीसी ढांचे के भीतर, संयुक्त अरब अमीरात ने न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देशों सहित कई देशों के साथ जीसीसी मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, वर्तमान में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत, तुर्की और मर्कोसुर सदस्य देशों यानी अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे सहित कई देशों और व्यापार समूहों के साथ समन्वय चल रही है।

परिणामत:, इसने इजरायल में निवेश शुरू कर दिया है; एक प्रमुख अमीराती संप्रभु धन कोष ने इजरायल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यम पूंजी फंड में अमरीकी डॉलर 100 बिलियन का निवेश किया है। अबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मैंग्रोव कैपिटल पार्टनर्स, एंट्रे कैपिटल, एलेफ कैपिटल, वियोला वेंचर्स, पिटंगो और मिज़मा सहित छह इजरायल-आधारित या केंद्रित उद्यम पूंजी फर्मों में अमरीकी डॉलर 20 मिलियन तक का निवेश किया। संयुक्त अरब अमीरात ने अफ्रीका में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया है और 2021 में, दुबई स्थित रसद फर्म डीपी वर्ल्ड ने अगले कुछ वर्षों में पूरे अफ्रीका में बुनियादी ढांचे में अमरीकी डॉलर 1 बिलियन से अधिक का निवेश करने का वचन दिया है। संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन ने प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए अमरीकी डॉलर 100 मिलियन का निवेश कोष लॉन्च किया है। यूएई के वित्त मंत्रालय और इराक के राष्ट्रीय निवेश आयोग ने पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेबनान में कुल एफडीआई का 11 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि अमीराती संस्थाएं सीरिया में निवेश परियोजनाओं का आकलन कर रही हैं।

ऊर्जा कूटनीति यूएई की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाइड्रोकार्बन ने लंबे समय तक संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का गठन किया, हालांकि, अमीरात तेल संसाधनों को कम करने और तेल की कीमतों में गिरावट के परिणामों को दूर करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है। दुनिया के अन्य हिस्सों में तेल जमा की महत्वपूर्ण खोज, तकनीकी प्रगति के कारण शेल तेल

के उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा के वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग की व्यवहार्यता अन्य कारक हैं जिन्होंने अमीरात को आर्थिक विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। यूएई की एशियाई देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी है और जापान, चीन, भारत, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया को तेल निर्यात करता है। इन देशों में ऊर्जा की मांग निकट भविष्य में कम होने की आशा नहीं है और भारत और चीन को इस क्षेत्र में अधिकांश विकास को चलाने की भविष्यवाणी की गई है। हाइड्रोजन ऊर्जा ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चीन, ग्रीस और अन्य देशों के साथ संयुक्त अरब अमीरात की ऊर्जा साझेदारी का एक और पहलू है।

अंत में, संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़े विलवणीकरण बाजारों में से एक है और दक्षिण कोरिया के साथ विलवणीकरण संयंत्रों पर एक संयुक्त अध्ययन कर रहा है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल-मजरूई ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात जल विलवणीकरण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इजरायल के साथ सहयोग कर सकता है क्योंकि ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी बिजली का 44 प्रतिशत उत्पन्न करना चाहता है। फरवरी 2022, जिसमें कहा गया था कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार की संभावना बहुत अधिक है और इसमें जल विलवणीकरण, शुद्धिकरण, संरक्षण और स्मार्ट प्रबंधन सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।

ङ) सुरक्षा और सहायता

संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। महासंघ के गठन के बाद से रक्षा और सुरक्षा प्रमुख चिंताएं हैं। शेख जायेद बिन सुल्तान अल-नाहयान राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम देशों के साथ संबंध बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक सुदृढ़ रक्षा क्षमता विकसित करना चाहते थे। वह द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में रक्षा कूटनीति की क्षमता में विश्वास करते थे, लेकिन इस बात से अवगत थे कि यह एक सुदृढ़ राष्ट्रीय रक्षा बल द्वारा समर्थित होने पर सबसे कुशल था। उन्होंने सशस्त्र बलों को कौशल विकास के स्रोत और अंतर्राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में देखा और इसलिए अबू धाबी वायु सेना विकसित करने की योजना बनाई। पड़ोस के बड़े राज्यों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने बड़े और अच्छी तरह से सुसज्जित सशस्त्र बल की आवश्यकता को समझा।

> वर्तमान में, संयुक्त अरब अमीरात की सेना को जीसीसी देशों में सबसे सक्षम बल माना जाता है और अमीरात को छोटे स्पार्टा के रूप में जाना जाता है जो एक कठिन पड़ोस में अपनी शक्ति से ऊपर है।

वर्तमान में, संयुक्त अरब अमीरात की सेना को जीसीसी देशों में सबसे सक्षम बल माना जाता है और

अमीरात को छोटे स्पार्टा के रूप में जाना जाता है जो एक कठिन पड़ोस में अपने वजन से ऊपर है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार आयात भागीदार भी है और कुल हथियार निर्यात का लगभग 55 प्रतिशत आयात करता है। 2021 में, बिडेन प्रशासन ने संकेत दिया कि वह 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 50 एफ-35 विमानों की 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हथियारों की बिक्री के साथ आगे बढ़ेगा, 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 18 एमक्यू-9 बी सशस्त्र ड्रोन और यूएई को हवा से हवा और हवा से जमीन के लिए गोला-बारूद के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज के साथ आगे बढ़ेगा। खाड़ी युद्ध के बाद, अमीरात ने अन्य देशों के साथ रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की और शेख जायेद अल-नाहयान ने संयुक्त अरब अमीरात में रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को उत्प्रेरित किया। एक सुदृढ़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात ने कई देशों के साथ रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं; उदाहरण के लिए, अमेरिका और यूएई ने 1987 के सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा, 2006 के अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते और 2019 रक्षा सहयोग समझौते सहित कई रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा समन्वय लगातार बढ़ रही है और सेवा प्रमुखों के स्तर पर नियमित रूप से उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुए हैं। तुर्की और यूएई ने रक्षा के लिए दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग सहयोग और अमीरात भी फ्रांस और इंडोनेशिया के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए चर्चा कर रहे हैं।

इसी तरह, संयुक्त अरब अमीरात पड़ोस और उससे परे के देशों के साथ सुदृढ़ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में सहायता कूटनीति का अनुसरण कर रहा है। सहायता, जो संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक शेख जायेद अल-नाहयान द्वारा परोपकार के कार्य के रूप में शुरू हुई थी, वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद के तहत यूएई की सॉफ्ट पावर के विस्तार के लिए एक उपकरण में बदल गई है। शेख जायेद चाहते थे कि दुनिया यूएई को अपने संसाधनों के एक योग्य प्रबंधक के रूप में देखे, पूरी दुनिया के लिए खुला और ग्रहणशील और राजनीतिक मध्यस्थता और विदेशी सहायता के माध्यम से यूएई का कद बढ़ाए। 1974 में, अबू धाबी की विदेशी सहायता इसकी कुल आय का 28 प्रतिशत थी। शेख जायेद दीर्घकालिक परिणामों में रुचि रखते थे और यमन में मारिब बांध के पुनर्निर्माण के लिए धन प्रदान करते थे। वह भाईचारे के विचार में विश्वास करते थे और इसे रक्त और रिश्तेदारी संबंधों, और अरब और इस्लामी पहचान से मानव जाति और मानवता तक विस्तारित करते थे। 1990 में, उन्होंने इराकी आक्रमण से भागने वाले कुवैतियों को वित्तीय सहायता और आवास प्रदान किया. हालांकि, वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात की विदेशी सहायता ब्रांडिंग का समर्थन करने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने के एक मौलिक तत्व के रूप में उभरी है. विदेशी सहायता संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के एक स्तंभ के रूप में उभरी है और इसमें अंतरराष्ट्रीय वातावरण को आकार देने की क्षमता है।

च) क्षेत्रीय पर्यावरण

जीसीसी का गठन प्रमुख क्षेत्रीय घटनाक्रमों में से एक था जिसका संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा। ईरान-इराक युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी में टैंकर हमलों की तीव्रता से चिंतित, यूएई ने

1981 में ओमान, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के साथ मिलकर जीसीसी का गठन किया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना था। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी सैन्य बलों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हुए 1990 में कुवैत पर इराक के आक्रमण की निंदा करने में जीसीसी राज्यों में शामिल हो गया। इसने कुवैत की मुक्ति के लिए सैनिकों का भी योगदान दिया। जीसीसी राज्यों द्वारा समर्थित, संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान द्वारा अबू मूसा और तुम्ब्स के विवादित द्वीपों पर नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर आपत्ति जताई। जैसे ही अरब स्प्रिंग खाड़ी देशों में पहुंचा और बहरीन और ओमान जैसे देशों में विरोध प्रदर्शन हुए, जीसीसी सदस्यों का समर्थन करने के अनुरूप, यूएई ने प्रभावित देशों को सैन्य सैनिक और वित्तीय सहायता भेजी। अरब वसंत के बाद के युग में, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पंखों को खोलना शुरू कर दिया और तत्काल पड़ोस से परे अपनी सक्रियता का विस्तार किया। यह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत (आईएसआईएल) के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले हवाई अभियान में शामिल हो गया, और 2014 में लीबिया में सीमित हवाई हमले भी किए। एक वर्ष बाद, यह यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गया।

ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिद्वंद्विता का असर यूएई की
विदेश नीति के गठन पर पड़ा है।

ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिद्वंद्विता का असर यूएई की विदेश नीति के गठन पर पड़ा है। एक छोटा राष्ट्र और एक नव स्थापित महासंघ होने के नाते, संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता के लिए विशाल पड़ोसी सऊदी अरब को अदालत में लाने का निर्णय किया और 1972 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। संबंध सुदृढ़ हुए और सऊदी अरब साझेदारी में एक प्रमुख नायक के रूप में उभरा। 1972 में किंग फैसल ने कहा कि अगर यूएई रूस के साथ संबंध स्थापित करता है तो अबू धाबी के क्षेत्र पर सऊदी दावे का कोई औपचारिक समाधान नहीं होगा। यूएई ने सऊदी अरब के अधीन भागीदार की भूमिका भी निभाई। 1973 में, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि संयुक्त अरब अमीरात ने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) के साथ संबंध स्थापित करने के निर्णय को निलंबित कर दिया ताकि सऊदी अरब को नाराज न किया जा सके। 1976 में, संयुक्त अरब अमीरात ने खाड़ी सुरक्षा पर सऊदी के रुख का समर्थन किया और सामूहिक सुरक्षा समझौते के लिए ईरान के शाह के प्रस्ताव का दो बार विरोध किया। एक वर्ष बाद, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने *अल-इत्तिहाद* में कहा कि यूएई की विदेश नीति सऊदी अरब से ली गई है।

सबसे बड़े जीसीसी देश के रूप में सऊदी अरब ने ईरान के प्रति सदस्य के दृष्टिकोण को आकार दिया। ईरानी क्रांति के खतरे का मुकाबला करने के उद्देश्य से सूचना मंत्री सम्मेलन (1979) का नेतृत्व सऊदी अरब ने किया था और ईरान के लिए जीसीसी सदस्य की भविष्य की प्रतिक्रिया के लिए स्वर निर्धारित किया था; इसने क्रांति को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने से लेकर सभी शियाओं से ईरानी शियाओं

तक ईरान की केवल एक पार्टी में डिमोट करने का निर्णय किया। हसन हमदान को दिए एक साक्षात्कार में, यूएई के एक अधिकारी ने कहा था कि सऊदी अरब के विशाल क्षेत्रीय आकार, आर्थिक और राजनीतिक पकड़ और यूएई की भौगोलिक स्थिति के कारण, सऊदी आयाम यूएई की विदेश नीति के मुख्य निर्धारकों में से एक है। इसी तरह, अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब और लेसर टुम्ब के तीन द्वीपों पर ईरान के कब्जे और अमीराती संघ से स्वतंत्र होने में दुबई को शाह के समर्थन ने यूएई को सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि ईरान ने फारस की खाड़ी के बजाय अरब खाड़ी शब्द के उपयोग का विरोध किया और रास अल-खैमा विवाद में ओमान का समर्थन किया, यूएई क्षेत्रीय विशाल सऊदी अरब के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित करने के लिए और इच्छुक हो गया। सऊदी अरब के साथ निकटता और ईरान के साथ ठंडे दृष्टिकोण की गतिशीलता जारी है। हालांकि, जैसा कि यूएई अपनी ताकत दिखा रहा है और बड़े वैश्विक क्षेत्र में प्रसार के लिए तैयार है, यह ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण सहित कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र रुख भी अपना रहा है। आर्थिक और सुरक्षा विचारों के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात अमीराती शिया समुदाय की उपस्थिति के बारे में विचारशील है और ईरान के प्रति इसके नरम रवैये के संकेत हैं।

इजरायल-फिलिस्तीनी और यमन संघर्ष क्षेत्रीय वातावरण के उल्लेखनीय उदाहरण हैं जो अधिक स्वतंत्र दृष्टिकोण की दिशा में यूएई की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अमीरात यमन में संलग्न हैं; इसने यमन की सरकार की वैधता का समर्थन करने के लिए एक्जियोनल ऑपरेशन में भाग लिया और हूती विद्रोहियों से निपटने में मदद करने के लिए राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी के अनुरोध का प्रत्युत्तर दिया। इसने अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा (एक्यूएपी) के खिलाफ सैन्य अभियानों में अमेरिका के साथ काम किया और अक्तूबर 2019 में यमन में अपनी सैन्य भागीदारी समाप्त कर दी। इसने यमनी लोगों को सहायता और आपातकालीन सहायता प्रदान करना जारी रखा और मानता है कि केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया ही स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है। हालांकि, जनवरी 2022 में हूती ड्रोन द्वारा मुसफ्फाह औद्योगिक क्षेत्र और अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अमीराती तेल सुविधाओं को निशाना बनाने से गतिशीलता बदल गई और यूएई में सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। 71 खाड़ी देश ने अमेरिका से हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित करने के लिए कहा है और वाशिंगटन ने घोषणा की है कि वह संयुक्त अरब अमीरात को निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस कोल और पांचवें नवीनतम के लड़ाकू विमान भेजेगा। यमन दलदल से बाहर आने के संघर्ष में, संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के करीब आ रहा है और उसने महसूस किया है कि उसे सुरक्षा और रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भरता के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण तैयार करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास का विदेश नीति के निर्णय लेने
पर सीधा प्रभाव पड़ता है और राष्ट्र विश्व व्यवस्था में चल रहे
परिवर्तनों के अनुसार नीतियां तैयार करते हैं।

शेख जायेद ने फिलिस्तीनी कारण के लिए एक वैचारिक समर्थन के साथ संयुक्त अरब अमीरात की विदेश

नीति की नींव का नेतृत्व किया; उन्होंने 1984 में उल्लेख किया कि पवित्र स्थानों की मुक्ति एक मुसलमान का सबसे बड़ा कर्तव्य था। हालांकि, खाड़ी सुरक्षा और फिलिस्तीन के प्रश्न के बीच संबंधों ने एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। अमेरिका के साझे मुद्दों का सहभाजन करते हुए महत्वपूर्ण खाड़ी किस्तों के लिए इजरायल की धमकी ने यूएई के लिए एक दुविधा पैदा कर दी और 2020 में उसने इजरायल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1971 से एक बड़ी छलांग लेते हुए, जब शेख जायेद ने अखबर अल-यौम से कहा कि कोई भी अरब देश ज़ायोनीवाद और इज़राइल के साथ लड़ाई के खतरों से सुरक्षित नहीं है; 2022 में यूएई का मानना है कि इजरायल के साथ एक समझौता अरब-इजरायल संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जो तनाव को कम करता है और पूरे क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लिए नई ऊर्जा पैदा करता है। यह अरब लीग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित दो-राष्ट्र समाधान की व्यवहार्यता को बनाए रखता है। यह आगे जोर देता है कि यूएई यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के फिलिस्तीनी अधिकार का दृढ़ता से बचाव करना जारी रखता है और नए समझौते के तहत, यूएई उस अंत के लिए बलपूर्वक वकालत करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करेगा।

छ) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण

राष्ट्र अन्य राज्यों से घिरे क्षेत्र में कार्य करते हैं और विदेश नीति जटिल नेटवर्क और वास्तविकताओं में पैंतरेबाज़ी करने का एक उपकरण है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास का विदेश नीति के निर्णय लेने पर सीधा प्रभाव पड़ता है और राष्ट्र विश्व व्यवस्था में चल रहे परिवर्तनों के अनुसार नीतियां तैयार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है और महासंघ ने बदलते वैश्विक गतिशीलता के अनुसार अपना दृष्टिकोण ढाला है। रूढ़िवादी खाड़ी शासनों की विफलता के खतरे और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले खाड़ी तेल पर सोवियत नियंत्रण की संभावना से प्रेरित, अमेरिका खाड़ी के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने और सैन्य समझौतों की स्थापना में सलंग्न है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) में शामिल होने और रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स के माध्यम से खाड़ी को सुपर पावर प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र में बदलने में अमेरिका की भूमिका की सामयिक आलोचना के बावजूद, संयुक्त अरब अमीरात ने महासंघ के गठन के बाद से अमेरिका का पक्ष लिया। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बावजूद सोवियत संघ को दुश्मन राष्ट्र नहीं माना। शेख जायेद ने 1981 में उल्लेख किया कि सोवियत संघ ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए कोई खतरा नहीं बनाया, हालांकि अमीराती विदेश मंत्रालय ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान में सोवियत बलों की उपस्थिति का विरोध किया।

शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद, वैश्विक व्यवस्था द्विध्रुवीय से एक-ध्रुवीय में बदल गई, जिसमें अमेरिका प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। हालांकि, बदलती वैश्विक भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के साथ कई देशों और ब्लॉक ने धीरे-धीरे प्रभुत्व प्राप्त किया। अमेरिका अपने आर्थिक प्रभुत्व,

सैन्य शक्ति और अचूकता के कारण एक प्रमुख शक्ति था; हालांकि, 2008 का वित्तीय संकट और अन्य देशों द्वारा सैन्य शक्ति का सापेक्ष लाभ अमेरिकी प्रभुत्व के क्षरण का संकेत है। इसके अलावा, उच्च जीवन स्तर के साथ-साथ विशाल आर्थिक संसाधनों और उन्नत सैन्य क्षमता के साथ, रूस एक महत्वपूर्ण नायक के रूप में उभरा है। ब्रिक्स और ईयू जैसे कुछ क्षेत्रीय समूह भी वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ आवाज के साथ शक्तिशाली ब्लॉक के रूप में उभरे हैं।

पश्चिम एशियाई क्षेत्र से अमेरिका की वापसी ने अन्य खाड़ी देशों के साथ संयुक्त अरब अमीरात को अन्य नायकों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए राजी किया है।

वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों ने यूएई की विदेश नीति को प्रभावित किया है। पश्चिम एशियाई क्षेत्र से अमेरिका की वापसी ने अन्य खाड़ी देशों के साथ संयुक्त अरब अमीरात को अन्य नायकों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए राजी किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने रूस के साथ सामरिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस क्षेत्र में जमीनी इस्लामी आंदोलनों के प्रति शत्रुता जैसे वैचारिक तालमेल को साझा किया है। उदाहरण के लिए, इसने सीरिया पर असद शासन की पकड़ को मान्यता दी और शासन के साथ अरब संबंधों को सामान्य बनाने की वकालत की। यूएई ने लीबिया में दाएश और अल-कायदा का मुकाबला करने के लिए रूस के साथ भी सहयोग किया है। संयुक्त अरब अमीरात दाएश और अल-कायदा जैसी ताकतों का मुकाबला करने के पक्ष में है और खलीफा हफ्तार और लीबिया नेशनल आर्मी (एलएनए) का समर्थन करने की रूसी स्थिति से सहमत है।

संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति का विकास

सप्रू
हाउस
पेपर

चित्र 3: संयुक्त अरब अमीरात की विदेश

संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति पांच दशकों की अवधि में विकसित हुई है और एक छोटे राष्ट्र के रूप में अमीरात की विदेश नीति पैंतरेबाज़ी के बारे में एक प्रवृत्ति उभरी है। जैसा कि चित्र 3 में दर्शाया गया है, संयुक्त अरब अमीरात पड़ोस से विस्तारित पड़ोस तक अपने प्रभाव के दायरे का विस्तार करने में सलंग्न है और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति है। यह जीसीसी सदस्यों के बीच सद्भावना बनाने के साथ शुरू हुआ और अन्य अरब देशों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद, अपने छोटे आकार को धता बताते हुए, संयुक्त अरब अमीरात की इस क्षेत्र से परे अपने प्रभाव का विस्तार करने की मंशा है।

क) संयुक्त अरब अमीरात और जीसीसी

संयुक्त अरब अमीरात जीसीसी का संस्थापक सदस्य बन गया जब इसे 1981 में रियाद में स्थापित किया गया था; इसके विशेष संबंधों, भौगोलिक निकटता, इस्लामी मान्यताओं पर आधारित समान राजनीतिक प्रणालियों, संयुक्त भाग्य और अन्य पांच सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्यों को देखते हुए। तब से, यह परिषद के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है; यूएई के वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने संयुक्त जीसीसी आर्थिक कार्रवाई के लिए एक एकीकृत आर्थिक समझौते को लागू किया है। अबू धाबी वित्तीय एकीकरण और मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्रासंगिक जीसीसी परियोजनाओं में भी सलंग्न है। यह जीसीसी सीमा शुल्क संघ और गल्फ कॉमन मार्केट के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। एमओएफ ने खाड़ी एकीकरण प्रक्रिया की दिशा में सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए खाड़ी मामलों के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद विभाग की स्थापना की है। यूएई जीसीसी संयुक्त एकीकरण को प्राप्त करने में सक्रिय रहा है और यह 2013 में सदस्य देशों के नागरिकों को अचल संपत्ति के मालिक होने और आर्थिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति देने वाला पहला सदस्य बन गया। इसके अलावा, यह जीसीसी देशों के नागरिकों को अपने सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए आकर्षित करने वाला दूसरा सदस्य था, जबकि सार्वजनिक शिक्षा का लाभ उठाने के लिए जीसीसी देशों के छात्रों का स्वागत किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात जीसीसी देशों के अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की मात्रा का 22 प्रतिशत हिस्सा है।

शुरुआती तीन दशकों के लिए, यूएई जीसीसी के पांच सदस्यों के साथ संबंध विकसित करने में सलंग्न था। अल-ऐन/बुराइमी क्षेत्र, जराराह/शायबा और खोर अल-उदैद की संप्रभुता पर सीमा विवादों के कारण सऊदी अरब ने 1974 तक संयुक्त अरब अमीरात की मान्यता रोक दी थी; यूएई प्रमुख पड़ोसी देश के साथ गर्मजोशी से संबंध विकसित करने का इच्छुक था। अबू धाबी के शासक शेख जायेद और दुबई के शासक शेख राशिद ने 1970 में सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की थी। शेख जायेद ने यूएई महासंघ के समेकन के लिए सऊदी समर्थन भी मांगा। 1973 में, तत्कालीन यूएई विदेश मंत्री अहमद बिन खलीफा अल-सुवैदी ने कहा कि सऊदी अरब के साथ संबंध बुराइमी प्रश्न से अधिक सुदृढ़ थे। 1974 की जेद्दा संधि और किंग फैसल के निधन के बाद किंग खालिद के शासन की शुरुआत ने दोनों पड़ोसियों के बीच गर्म संबंधों की शुरुआत को चिह्नित किया।

फेडरेशन के समेकन में यूएई की राजनीतिक कठिनाइयों ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी प्रारंभिक समन्वय पर एक अमिट छाप छोड़ी जो बाद में जीसीसी के सदस्य बन गए।

यूएई ओपेक के भीतर सऊदी क्षेत्रीय कूटनीति और नीति का एक सुदृढ़ समर्थक बन गया। बदले में, रियाद ने क्षेत्र के भीतर और बाहर से किसी भी खतरे के खिलाफ यूएई की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध किया। सऊदी अरब के साथ सुदृढ़ संबंध बनाने के लिए यूएई की खोज इतनी सुदृढ़ थी कि अबू धाबी ने आधिकारिक तौर पर 1975 में रियाद पर अपनी निर्भरता को स्वीकार किया। संयुक्त अरब अमीरात ईरान को यह दिखाने के लिए उत्सुक था कि वह सऊदी प्रभाव क्षेत्र के तहत था। 1976 में संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान अमीरात की अधिक एकता के लिए किंग खालिद का समर्थन और दिसंबर 1976 में दोहा में ओपेक की बैठक में तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए रियाद को अबू धाबी का समर्थन अन्य नौ सदस्यों द्वारा 15 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव के विपरीत दोनों पड़ोसियों के बीच सुदृढ़ संबंधों और आपसी निर्भरता का संकेत देता है।

फिर भी, ईरान में इस्लामी क्रांति ने दोनों देशों को विभिन्न पदों पर देखा; यूएई ने ईरान के लोगों द्वारा किए गए निर्णय का समर्थन किया जबकि सऊदी अरब ईरान के शाह के साथ खड़ा था। यूएई ने 1979 ओपेक की बैठक में सऊदी अरब से अलग नीति अपनाई और तेल की कीमतों में 80 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा करने वाले अन्य चार सदस्यों का पक्ष लिया। चल रही राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद, अब तक अबू धाबी ने विश्वास हासिल कर लिया था और खाड़ी में सुरक्षा कवच के रूप में स्थिति बनाए रखने के लिए खाड़ी देशों का समर्थन करने के लिए रियाद की मजबूरियों के बारे में निश्चित था। ईरान-इराक युद्ध के दौरान इराक को यूएई के समर्थन ने सऊदी अरब को यूएई को एक अलग परिप्रेक्ष्य के साथ देखने के लिए मजबूर किया और इसने अमीरात को एक सुदृढ़ महासंघ के साथ-साथ इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में मानना शुरू कर दिया।

फेडरेशन के समेकन में यूएई की राजनीतिक कठिनाइयों ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी प्रारंभिक समन्वय पर एक अमिट छाप छोड़ी जो बाद में जीसीसी के सदस्य बन गए। कुवैत जो संघ के गठन के दौरान मध्यस्थता में सक्रिय रूप से सलंग्न था, ने नौ सदस्यीय महासंघ (बहरीन और कतर सहित) के लिए प्रतिज्ञा की। यह नौ छोटे अमीरात के बीच राजनीतिक मतभेदों को दूर करने में सऊदी अरब के साथ शटल कूटनीति में भी सलंग्न था। फेडरेशन के गठन के दो दशक बाद, अमीरात ने 1990 में इराकी आक्रमण के दौरान कुवैत का समर्थन किया। यह कुवैत पर हमला करने की इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की योजनाओं का विरोध करने वाले पहले अरब देशों में से एक था। संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने एक साथ ओपेक

नियमों की अवहेलना की और बाजार को सस्ते तेल से भर दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने जमीन पर 2,000 सैन्य कर्मियों को प्रदान किया और कुवैत के लिए 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुदृढ़ वित्तीय सहायता के साथ-साथ संबद्ध बलों को क्षेत्र में सैन्य अड्डे स्थापित करने की अनुमति दी।

यूएई ने बहरीन के साथ सोहार्द संबंध बनाए रखा, हालांकि कतर के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे; कतर और बहरीन दोनों ने 1971 में महासंघ में शामिल होने की शर्त रखी थी। यूएई ने बहरीन की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जीसीसी के पेनिनसुला शील्ड फोर्स (पीएसएफ) में 600 पुलिसकर्मियों का योगदान दिया, जब प्रदर्शनकारियों ने 2011 में मनामा को अवरुद्ध कर दिया था। दोनों देशों ने मिलकर 2017 में कतर को अलग-थलग कर दिया था और साथ ही 2020 में इजरायल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यूएई ने बहरीन के राजकोषीय कार्यक्रम में निवेश किया है और दोनों देश अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग का विस्तार करते हुए कई संयुक्त परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। 2018 में, संयुक्त अरब अमीरात ने कुवैत और सऊदी अरब के साथ बहरीन के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की।

जीसीसी में तत्काल पड़ोसियों के बीच अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद, संयुक्त अरब अमीरात ने अन्य अरब देशों की ओर अपनी पहुंच का विस्तार किया।

यूएई-कतर विवाद 2017 में स्पष्ट हो गया जब अमीरात ने सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र के साथ ईरान के प्रति दृष्टिकोण, नामित आतंकवादी संगठनों को समर्थन और वित्त पोषण, अल-जज़ीरा और अन्य कतरी समाचार आउटलेट्स की अनजान रिपोर्टिंग और मित्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप सहित क्षेत्रीय नीतिगत मतभेदों पर कतर का बहिष्कार करने का फैसला किया। देशों ने 2021 में अल-उला घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ नाकाबंदी समाप्त कर दी; हालांकि, यूएई ने अभी भी कतर में अपना दूतावास फिर से नहीं खोला है। अबू धाबी ने मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड को कतर के समर्थन पर 2014 में दोहा में अपने राजदूत को वापस ले लिया था। विशेष रूप से, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान डॉल्फिन गैस परियोजना के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कतर संकट के दौरान संबंध टूटने के बाद भी पाइपलाइनों ने काम करना जारी रखा। यह ओमान में निवेशकों की जीसीसी और अरब सूची में सबसे ऊपर है। अबू धाबी और मस्कट ने अपने सीमा विवादों को हल किया और 2008 में सीमा को अंतिम रूप दिया। ओमान ने भी 2021 में इजरायल के साथ संबंधों के संयुक्त अरब अमीरात के सामान्यीकरण का समर्थन किया।

ख) क्षेत्रीय पदचिन्हों का विस्तार

जीसीसी में पड़ोसियों के बीच अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद, संयुक्त अरब अमीरात ने अन्य अरब देशों की ओर अपनी पहुंच का विस्तार किया। यूएई सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा रहा है जिसने सना में हादी सरकार को बहाल करने के लिए मार्च 2015 में यमन में हस्तक्षेप किया था। बहरहाल, इसने अलगाववादी दक्षिणी संक्रमण परिषद (एसटीसी) का समर्थन किया है जो अब अधिकांश अदन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यमन का यूएई के लिए सामरिक महत्व है क्योंकि इसके दक्षिणी क्षेत्र पर नियंत्रण बाब अल-मंडेब, अदन की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका में शक्ति प्रक्षेपण के लिए महत्वपूर्ण है।

इरिट्रिया में मेयुन द्वीप और असेब बंदरगाह पर एक सैन्य अड्डे की उपस्थिति, सोमालीलैंड में बेरबेरा बंदरगाह तक पहुंच के साथ-साथ एसटीसी के माध्यम से सोकोत्रा द्वीप पर नियंत्रण यूएई को प्रमुख शिपिंग मार्गों पर लाभ प्रदान करता है। 17 जनवरी 2022 को, मुसफ्फाह औद्योगिक क्षेत्र और अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अमीराती तेल सुविधाओं को ऑपरेशन तूफान यमन के तहत हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किए गए पंखों वाली कुद्स मिसाइलों और समद-3 ड्रोन द्वारा मारा गया था। इसमें दो भारतीय नागरिकों सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी। परिणामत:, संयुक्त अरब अमीरात और अरब लीग ने अमेरिका से हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित करने के लिए कहा।

इसी तरह, संयुक्त अरब अमीरात ने सीरियाई संकट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को आकार देने में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। दोनों देशों ने संघर्ष के चरम के दौरान भी द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा, नियमित उड़ानों ने असद के आंतरिक सर्कल के लिए शरण की पेशकश की। असद के पति आसिफ शावकत की हत्या के बाद खाड़ी देश उनकी बहन बुशरा का अर्ध-स्थायी निवास भी बन गया। दुबई अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान सीरिया के मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर था। सीरियाई व्यापारियों और राजनेताओं ने पेट्रो-राष्ट्र के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के शुरुआती उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त अरब अमीरात ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सीज़र प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया, सीरिया के क्षेत्रीय पुनर्वास की सुविधा प्रदान कर रहा है और कोविड-19 महामारी के प्रकाश में चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के हितार्थ, सीरिया लेबनान और इराक में ईरानी लाइन का पालन नहीं करता है। संघर्ष की शुरुआत में, संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया में अनुमोदित विद्रोही समूहों के लिए हथियार खरीदने के लिए धन के बहुपक्षीय पूल में योगदान दिया। हालांकि, 2018 में, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री ने स्वीकार किया कि सीरिया को अरब लीग से निष्कासित करना और दमिश्क के साथ राजनयिक संबंधों को काटना एक बड़ी गलती थी। 2021 में, संयुक्त अरब अमीरात ने दमिश्क में अपना दूतावास फिर से खोला और 2022 में, संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका की आलोचना के बावजूद सीरियाई राष्ट्रपति की मेजबानी की।

अपने आर्थिक संसाधनों और अरब वसंत के दौरान इस्लामी ताकतों से खतरे की धारणा के कारण क्षेत्रीय गतिशीलता में बढ़ते कद के साथ, संयुक्त अरब अमीरात ने पड़ोस से परे अपनी पहुंच का विस्तार किया।

संयुक्त अरब अमीरात ने सद्दाम युग के बाद बगदाद की ओर हाथ बढ़ाया और इराक के स्थिरीकरण के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, इराकी पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन मिशनों की मेजबानी की और पुनर्निर्माण गतिविधियों को वित्त पोषित किया। 2012 में, संयुक्त अरब अमीरात ने इराक के कुर्द-नियंत्रित स्वायत्त क्षेत्र में एक वाणिज्य दूतावास खोला। संयुक्त अरब अमीरात और अन्य जीसीसी राज्यों ने इराक को बिजली प्रदान करने और ईरानी आपूर्ति पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रस्ताव दिया है। 2020 में, संयुक्त अरब अमीरात ने कोविड-19 महामारी से निपटने में इराक की मदद करने के लिए उपकरणों के विमान वितरित किए।

ग) मध्य पूर्व से परे जाना

अपने आर्थिक संसाधनों और अरब वसंत के दौरान इस्लामी ताकतों से खतरे की धारणा के कारण क्षेत्रीय गतिशीलता में बढ़ते कद के साथ, संयुक्त अरब अमीरात ने पड़ोस से परे अपनी पहुंच का विस्तार किया। इसने अफ्रीकी देशों में एक सक्रिय विदेश नीति का अनुसरण किया जो 2018 में इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महत्वपूर्ण था। संयुक्त अरब अमीरात विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से बड़े अरबी बोलने वाले डायस्पोरा की मेजबानी करता है और सोमाली व्यवसायों के लिए एक प्रमुख बैंकिंग केंद्र है। इसकी एक रसद केंद्र और क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में उभरने की मंशा है और अबू धाबी बाब अल-मंदाब और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से समुद्री नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित किए बिना वांछित मॉडल प्राप्त नहीं कर सकता है। लाल सागर गलियारे के साथ सहयोग संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक सामरिक प्राथमिकता है; यह क्षेत्र में समुद्री डकैती विरोधी पहलों में सलंग्न है। संयुक्त अरब अमीरात ने सोमालिया के पुंटलैंड के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र में एक समुद्री पुलिस बल को प्रशिक्षित किया और इस्लामी अल-शबाब विद्रोह के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया।

2017 के खाड़ी संकट ने दोनों पक्षों के नेताओं को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में गठबंधन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। तब से, यूएई ने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है और विशेष रूप से लाल सागर के साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया है।

चूंकि 2011 में अरब वसंत ने इस क्षेत्र को घेर लिया था, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात ने लाल सागर तट के साथ देशों को वाणिज्यिक और सामरिक भागीदारों के रूप में देखना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय अस्थिरता, ईरान का बढ़ता प्रभाव, सोमालिया से उत्पन्न समुद्री डकैती और यमन में युद्ध ने सामूहिक रूप से एक स्थिर लाल सागर गलियारे को अनिवार्य कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात इस्लामवादियों और मुस्लिम ब्रदरहुड को अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है और उत्तरी अफ्रीका में उनके उत्थान ने यूएई को मिस्र और लीबिया में अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी को अपदस्थ किए जाने की सराहना की गई जो फरवरी 2011 में होस्नी मुबारक को सत्ता से बेदखल करने के बाद 2012 में मिस्र के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। लीबिया में संयुक्त अरब अमीरात ने 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को उखाड़ फेंकने में सशस्त्र लीबियाई विद्रोहियों की मदद के लिए हवाई हमले करने में कई खाड़ी देशों के साथ मिलकर काम किया था। उसने पूर्वी लीबिया स्थित खलीफा हाफ्टर के एलएनए के समर्थन में हथियार भी भेजे। ट्यूनीशिया में एन्नाहदा नेता रचेद घननौची ने आरोप लगाया है कि संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति कैस सैयद की कार्यकारी शक्तियों के व्यापकीकरण का समर्थन कर रहा है और ट्यूनीशिया के 2011 के लोकप्रिय विद्रोह के मद्देनजर अपनाए गए संविधान के निलंबन का समर्थन करता है।

2017 के खाड़ी संकट ने दोनों पक्षों के नेताओं को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में गठबंधन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। तब से, यूएई ने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है और विशेष रूप से लाल सागर के साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया है। खाड़ी संकट के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद फरमाजो की सोमाली सरकार को कतर के करीब माना और सोमालिया के संघीय राज्यों और सोमालीलैंड गणराज्य की सरकारों का समर्थन किया। राजनीतिक गठबंधन, सहायता, निवेश और बंदरगाह अनुबंधों की मदद से, संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीका में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इरिट्रिया-इथियोपिया शांति समझौते में इसकी भूमिका के साथ-साथ इथियोपिया और मिस्र के बीच तनाव को कम करने से अफ्रीका में यूएई के कद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में बढ़ाने में मदद मिली है। संयुक्त अरब अमीरात ने इथियोपिया के नए शासक अबी अहमद के साथ अच्छे संबंध विकसित किए हैं और सहायता और निवेश में 3 बिलियन अमरीकी डॉलर का वचन दिया है।

तालिबान के साथ यूएई का जुड़ाव इस क्षेत्र के बाहर अपनी पहुंच का विस्तार करने की अमीरात की इच्छा का एक और उदाहरण है। 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों से पहले, यूएई तालिबान आंदोलन

को खतरे के रूप में नहीं देखता था। यह पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ 1996-2001 के दौरान तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता देने वाले तीन देशों में से एक था। हालांकि, 11 सितंबर के हमलों के बाद, अमीरात ने तालिबान विरोधी रुख अपनाया और अमेरिका को अफगानिस्तान में संचालन के लिए अपनी सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात तालिबान के बाद अफगानिस्तान को सहायता का दाता था। फिर भी, अमीरात ने 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया और अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी का निर्वासन में रहने के लिए स्वागत किया। वर्तमान में, इसने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोल दिया है और अगस्त 2021 में काबुल से निकाले गए कई हजार अफगानों की मेजबानी कर रहा है।

क्षेत्र के भीतर और बाहर अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए,
यूएई अपनी विदेश नीति के संबंध में साहसिक कदम उठाने से
पीछे नहीं हट रहा है।

घ) एक छोटे राष्ट्र के रूप में यूएई के साहसिक कदम

क्षेत्र के भीतर और बाहर अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए, यूएई अपनी विदेश नीति के संबंध में साहसिक कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति 2010 के दशक के दौरान कई साहसिक, और यहां तक कि विवादास्पद कदमों के साथ आई, जैसे कतर को अवरुद्ध करना, यमन रणनीति पर सऊदी अरब के साथ टूटना, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना, यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका के साथ गठबंधन नहीं करना, अधिक स्वतंत्रता को रेखांकित करना।

दो बड़े पड़ोसियों, सऊदी अरब और ईरान के साथ इसके संबंध धीरे-धीरे अधिक तर्कसंगत और कम अधीनस्थ हो गए हैं। सऊदी अरब के साथ, संबंधों को भाईचारे की साझेदारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन अबू धाबी कई मुद्दों पर अपने मतभेदों को व्यक्त करने और एक अलग दृष्टिकोण अपनाने से पीछे नहीं हटा है। उदाहरण के लिए, 2009 में, संयुक्त अरब अमीरात ने जीसीसी मुद्रा और मौद्रिक संघ की सऊदी परियोजना का विरोध किया, जब यह मौद्रिक एजेंसी की मेजबानी करने की लड़ाई हार गया। यमन में, शुरू में सऊदी अरब में शामिल होने के बाद, संयुक्त अरब अमीरात एसटीसी का समर्थन करने और सक्रिय लड़ाई से पीछे हटने की एक स्वतंत्र नीति को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी स्थिति से हट गया। 2021 में, यूएई ने तेल उत्पादन बढ़ाने पर सऊदी अरब के साथ विवाद किया; जबकि अधिकांश ओपेक+सदस्यों ने अगले वर्ष के अंत तक हर महीने 400,000 बीपीडी द्वारा उत्पादन को बढ़ाकर महामारी के मद्देनजर तेल उत्पादन पर कटौती को कम करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, संयुक्त अरब अमीरात ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया जब तक कि इसका व्यक्तिगत उत्पादन कोटा नहीं

बढ़ाया गया।

यूएई की क्षेत्रीय पैंतरेबाजी ने उसे एक स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने और अमेरिका के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़े होने की ताकत दी है। इसने यूक्रेन संकट पर अमेरिकी लाइन का पालन नहीं किया और संकट पर प्रतिक्रिया देने में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।

साथ ही, दुश्मनी से परिभाषित संबंधों के बावजूद, यूएई ने ईरान के साथ संबंधों में सामान्य स्थिति लाने के लिए कदम उठाए हैं। ईरान के संबंध में समस्याएं और खतरे की धारणा गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। 1971 में संयुक्त अरब अमीरात को मान्यता देने से पहले, ईरानी सरकार ने यूएई महासंघ के प्रस्ताव पर हमला करते हुए कहा था कि यह विदेशी हस्तक्षेप और ब्रांडेड शक्तियों की हिंसक नीतियों पर आधारित था। 1976 में, ईरान ने खाड़ी की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अधिक महत्व देना शुरू कर दिया और एक ऐसा संबंध विकसित किया जिसमें मित्रता की झलक थी। हालांकि, यूएई क्रांति के बाद ईरान के प्रति सतर्क हो गया और ईरान-इराक युद्ध के दौरान चुपचाप बगदाद का समर्थन किया। यूएई ने ईरान परमाणु समझौते से 2018 में अमेरिका की वापसी और अधिकतम दबाव की नीति के आवेदन का समर्थन किया। हालांकि, 2019 के मध्य में, ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में यूएई की सुरक्षा के लिए जोखिम के बारे में चिंतित, यूएई नेतृत्व ने तेहरान को संलग्न करना शुरू कर दिया। दुबई ने अक्सर ईरान के साथ जुड़ाव की वकालत की है; इसमें बड़े ईरानी मूल के समुदाय के साथ-साथ एक व्यापक ईरानी वाणिज्यिक उपस्थिति भी है। जुलाई 2022 में, अमीराती और ईरानी विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर समन्वय की और संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की; यूएई कथित तौर पर तेहरान में एक राजदूत को वापस भेजने पर विचार कर रहा है।

यूएई की क्षेत्रीय पैंतरेबाजी ने उसे एक स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने और अमेरिका के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़े होने की ताकत दी है। इसने यूक्रेन संकट पर अमेरिकी लाइन का पालन नहीं किया और संकट पर प्रतिक्रिया देने में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी होने के बावजूद, संयुक्त अरब अमीरात ने यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप की निंदा करते हुए यूएनएससी में पेश प्रस्ताव में भाग नहीं लिया। दिसंबर 2021 में, यूएई ने एफ-35 विमान, रीपर ड्रोन और अन्य उन्नत युद्ध सामग्री खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को निरस्त करने की धमकी दी थी। संयुक्त अरब अमीरात का मानना था कि चीनी जासूसी से हथियारों की सुरक्षा के लिए अमेरिका द्वारा निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताएं कठिन थीं और अमीरात की राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डाल देंगी।

दूसरी बात, वाशिंगटन की नाराजगी के बावजूद, यूएई चीन के साथ जुड़ाव बढ़ा रहा है। 2021 में, अमेरिका ने अमीराती सरकार को चेतावनी दी थी कि उसके देश में चीनी सैन्य उपस्थिति दोनों देशों के बीच संबंधों को खतरे में डाल सकती है। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात में एक चीनी बंदरगाह पर एक सैन्य सुविधा के निर्माण के बारे में चिंतित था और अमीरात ने सुविधा को तुरंत बंद करने के लिए बाध्य किया। हालांकि,

ऐसा लगता है कि यूएई चीन के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार कर रहा है। देश ने कथित तौर पर चीन से सशस्त्र यूएवी खरीदे हैं और लीबिया में हमले के लिए उनका इस्तेमाल किया है। यह बीआरआई के तहत चीन से निवेश भी स्वीकार कर रहा है। अप्रैल 2019 में, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने जेबेल अली बंदरगाह पर चीनी उत्पादों को स्टोर करने और शिप करने के लिए 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए। चीन कृषि में संयुक्त अरब अमीरात में निवेश कर रहा है; 2012 में, चीनी खेत मालिक ने नाजवा रेगिस्तान में सिंचाई प्रणाली स्थापित की, बाड़ स्थापित की और वातानुकूलित ग्रीनहाउस का निर्माण किया। जुलाई 2022 में, मोहम्मद बिन जायेद ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ जायेद से सम्मानित किया।

अंत में, फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े होने की अपनी आधिकारिक स्थिति से दूर, यूएई ने 2020 में इजरायल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति यूएई की नीति तीसरे सबसे पवित्र इस्लामी स्थल और अरब राष्ट्रवाद के रूप में यरूशलेम के महत्व पर आधारित है। 1972 में, शेख जायेद ने अपने निपटान में सभी संसाधनों के साथ अरब कारण के लिए यूएई के पूर्ण समर्थन की फिर से पुष्टि की। 1973 के युद्ध के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात ने चिकित्सा टीमों को भेजा, अरब युद्ध के मोर्चे का समर्थन करने के लिए अमरीकी डॉलर 100 मिलियन का दान दिया और इजरायल के बचाव में आने के लिए अमेरिका पर तेल प्रतिबंध में शामिल हो गया। बाद में, इसका उग्रवादी दृष्टिकोण शांति और समझौते में बदल गया।

2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, यूएई की आधिकारिक स्थिति एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करना था, और 2002 अरब शांति पहल के आधार पर इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का न्यायपूर्ण समाधान था। हालांकि, पिछले दशक की शुरुआत से, यूएई और इज़राइल करीब आने लगे। 2011 में, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल ने सिनाई प्रायद्वीप में उग्रवाद विरोधी अभियानों में मिस्र के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया और अगस्त 2020 में, इजरायल और यूएई ने कथित तौर पर सोकोट्रा द्वीप पर जासूसी ठिकाने स्थापित करने की योजना बनाई। समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों पक्ष राजदूतों का आदान-प्रदान करने और व्यापार, दूरसंचार और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजरायल का व्यापार 2021 में 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और दोनों पक्षों को 2031 तक द्विपक्षीय आर्थिक गतिविधि को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की आशा है।

संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति की बदलती गतिशीलता

ब्रूस डब्ल्यू जेन्टलसन ने अमेरिकी विदेश नीति पर अपनी पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला है कि जिन राष्ट्रीय हितों पर सुपर पावर अपनी विदेश नीति के निर्णयों को आधार बनाती है, वे शक्ति, शांति, समृद्धि और सिद्धांतों के चार मुख्य लक्ष्य हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश के लिए जो विशिष्ट विशेषताओं वाले क्षेत्र में स्थित है और राष्ट्र गठन की एक अलग प्रक्रिया से गुजरा है, मुख्य लक्ष्य अधिक व्यापक हैं। जनार्दन ने संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के गठन के चार और लक्ष्यों के रूप में प्रतिष्ठा, लाभ, व्यक्तित्व और प्रचार को जोड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात के मामले में, यह स्पष्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात के गठन के तुरंत बाद, इसकी विदेश नीति को शक्ति, शांति, समृद्धि और सिद्धांत के राष्ट्रीय हितों के अनुसार आकार दिया जाने लगा, हालांकि जायेद युग के बाद, प्रतिष्ठा, लाभ, व्यक्तित्व और प्रचार अधिक प्रमुख मुख्य लक्ष्यों के रूप में उभरे हैं।

क) जायेद युग:

संयुक्त अरब अमीरात की नींव के एक वर्ष बाद, शेख जायेद ने विदेश नीति के चार उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित किया और अगले तीन दशकों तक उनका पालन किया। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध और सहयोग बनाए रखना और सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीकों से भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाना था। दूसरा उद्देश्य अरब दुनिया और प्रारंभिक और मौलिक अरब सम्मेलनों के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता का पालन करना था। तीसरा उद्देश्य सभी क्षेत्रों में मुस्लिम राज्यों के साथ इस्लामी एकजुटता और सहयोग में सुधार करना था। और चौथा उद्देश्य सुरक्षा, शांति और प्रगति स्थापित करने के लिए सभी क्षेत्रों में सभी देशों के साथ फलदायी सहयोग बनाए रखना था।

यह स्पष्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात के गठन के तुरंत बाद, इसकी विदेश नीति को शक्ति, शांति, समृद्धि और सिद्धांत के राष्ट्रीय हितों के अनुसार आकार दिया जाने लगा, हालांकि जायेद युग के बाद, प्रतिष्ठा, लाभ, व्यक्तित्व और प्रचार अधिक प्रमुख मुख्य लक्ष्यों के रूप में उभरे हैं।

शेख जायेद चाहते थे कि यूएई एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे, और महसूस किया कि इसे घरेलू अस्थिरता के साथ-साथ क्षेत्रीय और बाहरी हस्तक्षेपों से अलग रखने की आवश्यकता है।

शेख जायेद चाहते थे कि यूएई एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे, और महसूस किया कि इसे घरेलू अस्थिरता के साथ-साथ क्षेत्रीय और बाहरी हस्तक्षेपों से अलग रखने की आवश्यकता है।

शेख जायेद चाहते थे कि यूएई एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे, और महसूस किया कि इसे घरेलू अस्थिरता के साथ-साथ क्षेत्रीय और बाहरी हस्तक्षेपों से अलग रखने की आवश्यकता है। इसलिए, उन्होंने एक सुदृढ़ रक्षा बल के माध्यम से देश की संप्रभुता को बनाए रखने पर जोर दिया जो एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। यूएई के लिए आंतरिक समेकन महत्वपूर्ण था; एक छोटा राष्ट्र और एक नया महासंघ होने के नाते, संयुक्त अरब अमीरात को संघ के समेकन और सऊदी अरब जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से अंतर- और अंतर-संघीय विवादों के समाधान में मदद लेने में कोई हिचक नहीं थी।

जायेद की विदेश नीति के लिए शांति बनाए रखना दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था। क्षेत्रीय विवादों में, तटस्थता अमीराती विदेश नीति की पहचान थी; ईरान-इराक युद्ध के दौरान यूएई के लिए पक्ष चुनना मुश्किल था क्योंकि दुबई, शारजाह और उम अल-कुवैन के ईरान के साथ अनुकूल संबंध थे, जबकि अबू धाबी, फुजैरा, रास अल-खीमाह और अजमान का झुकाव इराक की ओर था। इसके अलावा यूएई ने नरम शक्ति के प्रचार के लिए उपकरण के रूप में मध्यस्थता और विदेशी सहायता का इस्तेमाल किया; शेख जायेद ने ईरान-इराक युद्ध, कुवैत पर इराक के आक्रमण, बहरीन और कतर के बीच क्षेत्रीय विवाद (1990) और 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान मध्यस्थता प्रयासों का नेतृत्व किया। संयुक्त अरब अमीरात ने दिसंबर 1971 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने से महीनों पहले जुलाई 1971 में अरब आर्थिक विकास के लिए अबू धाबी फंड बनाया और तब से इस क्षेत्र में विदेशी सहायता के माध्यम से नरम कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। पहले दो दशकों में विदेशी सहायता अमीराती सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत थी और इसका अधिकांश हिस्सा अरब दुनिया द्वारा प्राप्त किया गया था।

जायेद युग के दौरान समृद्धि यूएई की विदेश नीति का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ था। वह जानते थे कि किसी देश की समृद्धि उसकी दीर्घायु के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। आर्थिक स्थिरता एक प्रमुख विचार था जब यूएई जीसीसी के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गया। जीसीसी चार्टर के अनुसार, परिषद का मूल उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर-संबंध है। यह अर्थव्यवस्था, वित्त, व्यापार, सीमा शुल्क, पर्यटन, कानून और प्रशासन में समान नियमों के निर्माण पर भी जोर देता है। इसके अलावा, चार्टर में उद्योग, खनन, कृषि, जल और पशु संसाधनों में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के बारे में भी उल्लेख किया गया है। चार्टर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, संयुक्त उद्यम स्थापित करने और निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों पर जोर देता है। दशकों से, जीसीसी ने इस क्षेत्र के साथ-साथ उससे परे यूएई की नीतियों के लिए आधार बनाया।

सिद्धांत यूएई की विदेश नीति का चौथा स्तंभ था। आजादी के बाद, संयुक्त अरब अमीरात का उद्देश्य अखिल अरबवाद और अखिल इस्लामवाद के आदर्शों का पालन करने के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्याय का समर्थन करना था। इसने अरब और फिलिस्तीनी कारण के समर्थन में 1973 के तेल प्रतिबंध में भाग लिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त अरब अमीरात की राजनीति आदिवासीवाद और इस्लाम से प्राप्त राजनीतिक संस्कृति की निशानी है। यूएई के संस्थापक शेख जायेद पर आदिवासी समाज और इस्लाम की विशेषताओं का एक बड़ा प्रभाव था, और यह यूएई की विदेश नीति के आधार में दृढ़ता से दर्शाता है। शेख जायेद ने उल्लेख किया कि संयुक्त अरब अमीरात को मुसलमानों को एकजुट करना चाहिए और सम्मेलनों और इस्लामी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी के माध्यम से उनके कारणों का समर्थन करना चाहिए।

ख) ज़ायेद युग के बाद:

जायेद युग के बाद का समय यूएई के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। तीन दशकों में, दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव हुए और यूएई एक अपवाद नहीं था। जायेद युग के बाद, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति परिपक्व हो गई है और अमीरात अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत बढ़ा रहा है, जबकि प्रतिष्ठा, लाभ, व्यक्तित्व और प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 21वीं सदी नेताओं की युवा पीढ़ियों के सत्ता में आने या कई देशों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने के साथ शुरू हुई। युवा नेता साहसी विचारों के साथ आए थे और पुरानी पीढ़ी के नेताओं की तुलना में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक थे। उदाहरण के लिए, बशर अल-असद दमिश्क स्प्रिंग के रूप में बड़े बदलाव के वादे के साथ सीरिया में सत्ता में आए।इसी तरह, युवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं। संयुक्त अरब अमीरात के मामले में, हालांकि 2004 में शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान के निधन के बाद राष्ट्र पर शेख खलीफा बिन जायेद बिन नाहयान का शासन था; यह स्पष्ट है कि शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान 21वीं सदी में संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति के वास्तविक वास्तुकार थे। जुलाई में शेख खलीफा के निधन के बाद 2022 में यूएई के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले भी यूएई पर उनकी काफी पकड़ थी। मोहम्मद बिन जायेद के दृष्टिकोण ने यूएई के विकास को इस हद तक निर्देशित किया कि यूएई उनका पर्याय बन गया।

जायेद युग के बाद, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति परिपक्व हो गई है और अमीरात अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत बढ़ा रहा है, जबकि प्रतिष्ठा, लाभ, व्यक्तित्व और प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

i) क्षमता निर्माण और प्रक्षेपण

सदी के पहले दशक के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात ने क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और यह नेता द्वारा लिए गए विदेश नीति के निर्णयों में परिलक्षित होता है। क्षमता निर्माण का कार्य खाड़ी देश के लिए आर्थिक लाभ में वृद्धि करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने मानव संसाधन क्षमताओं और नेतृत्व विकास में निवेश करके अपने नागरिकों के बीच क्षमता विकसित करने का इरादा किया। उदाहरण के लिए, इसने कुशल राष्ट्रीय मानव पूंजी द्वारा सक्षम एक प्रतिस्पर्धी ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले दो दशकों के लिए एक रणनीति बनाई जो भविष्य में विदेशियों को काम पर रखने पर खर्च किए गए धन को बचाएगी। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, यूएई सेंट्रल बैंक ने अपने करियर विकास रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कर्मचारियों की क्षमताओं और कौशल में सुधार करने की दिशा में काम किया। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन और सीरिया जैसे अन्य ओआईसी देशों को तकनीकी ज्ञान प्रदान किया; और लीबिया और मॉरिटानिया के केंद्रीय बैंकों से टीमें प्राप्त कीं। संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक ने तुर्की, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नियामक अधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

क्षमता निर्माण का कार्य खाड़ी देश के लिए आर्थिक लाभ में वृद्धि करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।

21वीं सदी का दूसरा दशक संयुक्त अरब अमीरात के लिए क्षमता प्रक्षेपण के लिए समर्पित था। अबू धाबी सरकार ने अमीरात की अर्थव्यवस्था के परिवर्तन और विविधीकरण के लिए अबू धाबी आर्थिक दृष्टि 2030 की घोषणा की। दीर्घकालिक योजना का उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के स्रोत के रूप में तेल क्षेत्र पर निर्भरता को कम करना और भविष्य में ज्ञान-आधारित उद्योगों पर अधिक जोर देना है। कार्यक्रम ने सरकार के लिए तत्काल आर्थिक प्राथमिकताओं के क्षेत्रों की पहचान की। इसने एक खुले, कुशल, प्रभावी और विश्व स्तर पर एकीकृत कारोबारी माहौल के निर्माण पर जोर दिया; और एक अनुशासित राजकोषीय नीति को अपनाना जो आर्थिक चक्रों के प्रति उत्तरदायी है। इसने श्रम बाजार की दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए मुद्रास्फीति के प्रबंधनीय स्तर के साथ एक लचीला मौद्रिक और वित्तीय बाजार वातावरण स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसने प्रत्याशित आर्थिक विकास का समर्थन करने में सक्षम पर्याप्त और लचीला बुनियादी ढांचा विकसित करने और एक अत्यधिक कुशल, अत्यधिक उत्पादक कार्य बल विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया। अंत में इसने वित्तीय बाजारों को आर्थिक क्षेत्रों और परियोजनाओं के प्रमुख वित्त-पोषक बनने में सक्षम बनाने पर जोर दिया।

ii) कोविड-19 और चिकित्सा कूटनीति

21वीं सदी का तीसरा दशक कोविड-19 महामारी के साथ शुरू हुआ, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया और यूएई मानवीय प्रयासों में सक्रिय रूप से सलंग्न था। संयुक्त अरब अमीरात वैश्विक मानवीय पहलों तक पहुंचने और समर्थन करने वाले पहले देशों में से एक था और नॉवल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे देशों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का 80 प्रतिशत इसकी सहायता के लिए जिम्मेदार था। जुलाई 2021 तक, यूएई ने दुनिया भर के 135 देशों को कुल 2,154 टन चिकित्सा सहायता, वेंटिलेटर, स्क्रीनिंग उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और परीक्षण किट भेजे थे। यह सूडान, मॉरिटानिया, सिएरा लियोन, लेबनान और जॉर्डन के छह फील्ड अस्पतालों और तुर्कमेनिस्तान में 1 पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल क्लिनिक की स्थापना में सलंग्न था। संयुक्त अरब अमीरात ने डब्ल्यूएचओ को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता भी प्रदान की महामारी के दौरान यूएई के सक्रिय दृष्टिकोण, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को उनके संबंधित देशों में वापस भेजने में इसकी सहायता ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएई का कद और प्रतिष्ठा बढ़ा दी।

संयुक्त अरब अमीरात ने हाल के वर्षों में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया है और यह इसकी विदेश नीति के दृष्टिकोण में बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। यूएई अब एक प्रतिक्रियाशील बल होने से संतुष्ट नहीं है; यह विदेश नीति में सक्रिय कदम उठा रहा है। पिछले भाग में चर्चा किए गए साहसिक उपायों ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक सक्रिय और मुखर राष्ट्र की छवि बनाई है। यह नैतिक कम्पास के माध्यम से चीजों को समझने के बजाय अपने हितों के अनुसार मुद्दों और घटनाओं का मूल्यांकन करने में आदर्शवादी प्रवृत्तियों से यथार्थवाद की ओर बढ़ रहा है। नए नेता चल रहे क्षेत्रीय और वैश्विक बदलती गतिशीलता के प्रति सचेत हैं और साहसिक कदम उठाने और संबंधित जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव संयुक्त अरब अमीरात की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दिखाई दे रहा है; 2020 में इसका सकल घरेलू उत्पाद 359 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

iii) छवि प्रक्षेपण

हार्ड कोर बदलावों के साथ-साथ यूएई सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर भी फोकस कर रहा है। यह सामाजिक स्तर पर बदलाव ला रहा है जिसका प्रभाव क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच ने यूएई के लिए एक उदार छवि बनाई है। यूएई एमईएनए क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए भुगतान किए गए माता-पिता की छुट्टी शुरू करने वाला पहला देश बन गया और 57.5 प्रतिशत की महिला श्रम भागीदारी दर एमईएनए में सबसे अधिक में से एक है। इसी तरह समाज के लिए एक समग्र धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण संयुक्त अरब अमीरात को एक ऐसे देश के रूप में चित्रित करता है जो अन्य धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए तैयार है। यह न केवल अधिक निवेश को आकर्षित करता है, बल्कि यूएई को दुनिया भर के लोगों के लिए पिघलने वाले बर्तन के रूप में भी दर्शाता है। संयुक्त अरब अमीरात में 64 से अधिक वर्षों से दुबई शिव और कृष्ण मंदिर है और अक्तूबर 2022 में

दशहरा के अवसर पर जेबेल अली गांव में 'सिंधु गुरु दरबार मंदिर' नामक पहला बड़ा, स्वतंत्र पारंपरिक मंदिर खोला गया है।

यूएई हार्ड कोर बदलावों के साथ-साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर भी फोकस कर रहा है। यह सामाजिक स्तर पर बदलाव ला रहा है जिसका प्रभाव क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है।

उदार संपत्ति और बुनियादी ढांचे के कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि खाड़ी देश व्यावसायिक कार्यालयों के लिए पहली प्राथमिकता के रूप में उभरता है। दुबई सरकार अधिकांश प्रकार की कंपनियों के लिए कोई कॉर्पोरेट कर प्रदान नहीं करती है, साथ ही कोई प्रत्यक्ष आय कर नहीं है और मुनाफे के प्रत्यावर्तन पर कोई सीमा नहीं है। नया कंपनी अधिनियम (2015) और नया एफडीआई कानून (2018) संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम हैं। नया एफडीआई कानून विदेशी निवेशकों को कुछ उद्योगों में काम करने वाली कंपनियों में 100 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देता है।

संयुक्त अरब अमीरात ने आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को अपराध घोषित करने के लिए कानून पारित किए हैं। उदाहरण के लिए, 2014 का संघीय कानून संख्या 7 आतंकवाद अपराधों का मुकाबला करने से संबंधित है, 2015 का संघीय डिक्री-लॉ नंबर 2 भेदभाव और घृणा का मुकाबला करने से संबंधित है, और 2012 का संघीय कानून संख्या 5 साइबर अपराधों का मुकाबला करने पर केंद्रित है। 2018 का संघीय डिक्री-लॉ नंबर 20 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और अवैध संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर जोर देता है। यद्यपि इसने खतरनाक समय का अनुभव किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने मुस्लिम ब्रदरहुड के उदय के साथ अपनी विदेश नीति को बदल दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि उसे इस क्षेत्र से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। परिणामस्वरूप, सकारात्मक छवि निर्माण ने संयुक्त अरब अमीरात को विभिन्न मंचों पर अन्य देशों के लिए मतदान करने से लेकर अपने लिए मतदान करने और विभिन्न मंचों पर जगह पाने की दृढ़ता प्रदान की। यह ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है और एससीओ में एक संवाद भागीदार है। इसके अलावा, इसने अपने पड़ोसी देशों से मध्यस्थता की मांग करने से क्षेत्रीय मुद्दों में मध्यस्थ बनने तक स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, खासकर अफ्रीका में।

iv) सुरक्षा और विदेश नीति में विविधता

सुरक्षा और विदेश नीति में विविधता लाना बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए,

वर्तमान में यूएई सुरक्षा विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसने महसूस किया है कि यह बहु-वेक्टर साझेदारी का युग है और किसी एक वैश्विक प्रमुख शक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने में अंतरराष्ट्रीय नायकों की विफलता ने यूएई को वैकल्पिक समर्थन प्रणाली की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। यह उपयुक्त विकल्पों की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर निर्भर है। यह भी मानता है कि क्षेत्रीय समस्याओं के लिए क्षेत्रीय समाधान की आवश्यकता है और इसे अकेले बाहरी नायकों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात विदेश नीति में सामरिक हेजिंग के विचार के लिए खुला है। आने वाले वर्षों में, संयुक्त अरब अमीरात अन्य उभरती शक्तियों के साथ गहरे आर्थिक सहयोग की ओर अग्रसर होगा।

पश्चिमी विकल्पों के नुकसान की भरपाई करने और अपनी विदेश नीति में विविधता लाने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात ने पूर्व की ओर देखना शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात तकनीकी प्रगति के मामले में एक मध्य शक्ति है और एशियाई देशों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है।

दक्षिण एशिया के साथ-साथ यूएई साझेदारी के लिए मध्य एशियाई देशों की ओर भी देख रहा है। यूएई कजाकिस्तान को देश की निवेश रणनीति के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में देखता है; देश में 200 से अधिक अमीराती कंपनियां काम कर रही हैं।

पश्चिमी विकल्पों के नुकसान की भरपाई करने और अपनी विदेश नीति में विविधता लाने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात ने पूर्व की ओर देखना शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात तकनीकी प्रगति के मामले में एक मध्य शक्ति है और एशियाई देशों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है। उदाहरण के लिए, यह भारत और चीन के साथ तकनीकी प्रगति और आर्थिक सहयोग पर सहयोग करने के लिए तैयार है। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समझौता ज्ञापन उद्योगों, अंतरिक्ष प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को

सुदृढ़ करने में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग ने सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञता और डेटा के आदान-प्रदान पर चीन के शेडोंग प्रांत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी को नए तेल के रूप में देख रहा है और योग्य एशियाई प्रवासी आवश्यक योग्यता रखते हैं और इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

दक्षिण एशिया के साथ-साथ यूएई साझेदारी के लिए मध्य एशियाई देशों की ओर भी देख रहा है। यूएई कजाकिस्तान को देश की निवेश रणनीति के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में देखता है; देश में 200 से अधिक अमीराती कंपनियां काम कर रही हैं। तुर्कमेनिस्तान अपने विशाल प्राकृतिक गैस भंडार और ईरान के उत्तर में संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात प्राकृतिक गैस निर्यातक के रूप में अश्गाबात की भविष्य की भूमिका पर नजर रखते हुए अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को देखता है। मुबाडाला ने उजबेकिस्तान में भी 10 अरब डॉलर के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ऊर्जा, विनिर्माण, कृषि, बुनियादी ढांचा और विकास क्षेत्र शामिल हैं। अस्ताना जून 2023 में जीसीसी और मध्य एशियाई देशों के पहले आर्थिक मंच की मेजबानी करेगा।

एक छोटे से खाड़ी राष्ट्र के रूप में, संयुक्त अरब अमीरात भारत को एक बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बनाने का इरादा रखता है। यह एक ऊर्जा बाजार के रूप में भारत को अनुकूल रूप से देखता है और हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर मौजूदा आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करना चाहता है। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के साथ-साथ आईटी उद्योग पर सहयोग करना भी है। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात भारत को खाद्य सुरक्षा में एक विश्वसनीय और स्थिर भागीदार के रूप में पाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने फार्म टू पोर्ट परियोजना (2015) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विशिष्ट अमीराती बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसलें उगाई जाएंगी। संयुक्त अरब अमीरात के साथ-साथ अन्य खाड़ी देशों में भारतीयों को उनकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और गैर-राजनीतिक प्रकृति के लिए सम्मानित किया जाता है।

अंत में, संयुक्त अरब अमीरात ने महसूस किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के सीमित लाभ हैं और त्रिपक्षीय, मिनीलेटरल और बहुपक्षीय साझेदारी भविष्य हैं। बहुध्रुवीय दुनिया में, महाद्वीपों में फैले विभिन्न विशिष्ट मुद्दों पर बहुपक्षीय साझेदारी फायदेमंद होगी। यूएई का मानना है कि मल्टी-नेटवर्क दुनिया के युग में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए खाड़ी, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने की आवश्यकता है। यूएई पड़ोस के साथ-साथ उससे परे कनेक्टिविटी के महत्व को भी समझता है। संयुक्त अरब अमीरात एतिहाद रेल विकसित कर रहा है जो 11 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ सऊदी सीमा से हिंद महासागर तट पर फुजैरा तक चलने वाली 1200 किलोमीटर की रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना है। यूएई पानी के नीचे रेल

नेटवर्क के माध्यम से मुंबई को फुजैरा शहर से जोड़ने की संभावना भी तलाश रहा है।

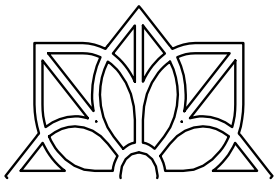

निष्कर्ष

सप्रू
हाउस
पेपर

एक राष्ट्र की विदेश नीति कई कारकों पर आधारित होती है और उत्तरार्द्ध का गहन अध्ययन राष्ट्र के अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यवहार के बारे में समझ विकसित करने में मदद करता है। संयुक्त अरब अमीरात एक छोटा और अपेक्षाकृत नवगठित राष्ट्र है लेकिन इसकी क्षेत्रीय और विदेश नीति की गतिशीलता इसे मध्य पूर्व में एक प्रतिष्ठित नायक बनाती है। भूगोल संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। खाड़ी में स्थित होने के कारण, देश खाड़ी एकजुटता का राग अलापता है। सीमा विवाद जारी रहने के कारण यूएई सुदृढ़ रक्षा नीति को आगे बढ़ा रहा है और रक्षा उद्देश्यों के लिए अपने संघीय बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित कर रहा है। सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय दिग्गज के साथ एक बड़ी सीमा साझा करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात एक अर्ध-स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है।

सामाजिक मैट्रिक्स और जनसांख्यिकीय रूपरेखा भी विदेश नीति के निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की आबादी 10 मिलियन के करीब है, जिसमें से केवल 12 प्रतिशत मूल निवासी हैं। इस प्रकार, प्रवासियों की उपस्थिति जो 88 प्रतिशत आबादी के बराबर है, संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू और विदेश नीति के गठन का एक प्रमुख निर्धारक है। संयुक्त अरब अमीरात गैर-अरब देशों से आने वाले प्रवासियों की तुलना में जीसीसी और अन्य अरब देशों से आने वाले प्रवासियों को प्राथमिकता देता है और यह श्रम कानूनों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, गैर-राष्ट्रीय जनसांख्यिकी प्रेषक देशों की तुलना में संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति को प्रभावित करती है; अमीरात और फिलीपीन ने 2021 में घरेलू श्रमिकों की भर्ती पर प्रतिबंध हटा दिया।

संयुक्त अरब अमीरात एक छोटा और अपेक्षाकृत नवगठित राष्ट्र
है लेकिन इसकी क्षेत्रीय और विदेश नीति की गतिशीलता इसे
मध्य पूर्व में एक प्रतिष्ठित नायक बनाती है।

इसी तरह जनता की राय में संयुक्त अरब अमीरात में विदेश नीति निर्णय लेने को आकार देने की शक्ति है। 1980 के ईरान-इराक युद्ध के दौरान, सद्दाम हुसैन ने ईरान के लिए पहली मांग के रूप में संयुक्त अरब अमीरात को तीन द्वीपों की बहाली की। ईरान को नाराज करने के लिए तैयार नहीं होने के बावजूद, जिसके साथ अबू धाबी और दुबई के घनिष्ठ संबंध थे, संघीय सरकार को इराक का समर्थन करना पड़ा क्योंकि यूएई अरब जनता की राय से अछूता नहीं था। किसी देश की राजनीतिक प्रणाली क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए विदेश नीति के निर्णयों के लिए एक और निर्धारक है। अमीरात के रूप में गठित होने से पहले, संयुक्त अरब अमीरात एक ब्रिटिश संरक्षक था और इसने शीत युद्ध की गतिशीलता में पश्चिमी ब्लॉक के करीब रखने के लिए नव स्वतंत्र यूएई की विदेश नीति को प्रभावित किया।

व्यक्तिगत नेताओं और उनके व्यक्तित्वों की भूमिका का भी संयुक्त अरब अमीरात में विदेश नीति के गठन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। 1980 और 1990 के दशक में शेख जायेद के नेतृत्व में, संयुक्त अरब अमीरात ने

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक मध्यमार्गी नीति का पालन किया, जिसमें क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थता को अपने केंद्र में रखा गया। हालांकि, वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के हॉब्सियन दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और राजनीतिक मतभेदों को हल करने के लिए एक उपकरण के रूप में सेना की दक्षता में विश्वास करते हैं। वह संयुक्त अरब अमीरात को पश्चिमी हिंद महासागर में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्रमुख वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र में बदलने का इरादा रखता है। वह दुबई के आर्थिक उदारवाद और अबू धाबी द्वारा लागू धर्मनिरपेक्ष अति-अधिनायकवाद के आधार पर मध्य पूर्व की क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को नया रूप देने का भी इरादा रखता है।

बदलते समय के साथ यूएई ने अपनी विदेश नीति को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर पड़ोस के साथ-साथ व्यापक क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने के लिए बदल दिया है।

आर्थिक परिवर्तन और सुधार विदेश नीति का एक और निर्धारक हैं और विदेशी निवेश में विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता है। जैसा कि यूएई अमीरात में निवेश करने वाले देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लाभों से अवगत है, यह अन्य देशों में निवेश के माध्यम से साझेदारी बढ़ाने के फलों से भी अच्छी तरह से परिचित है; परिणामत:, इसने इजरायल में निवेश शुरू कर दिया है। ऊर्जा कूटनीति यूएई की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाइड्रोकार्बन ने लंबे समय तक संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का गठन किया, हालांकि, अमीरात तेल संसाधनों को कम करने और तेल की कीमतों में गिरावट के परिणामों को दूर करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है।

बदलते समय के साथ यूएई ने अपनी विदेश नीति को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर पड़ोस के साथ-साथ व्यापक क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने के लिए बदल दिया है। शुरुआती तीन दशकों के लिए, यूएई जीसीसी के पांच सदस्यों के साथ संबंध विकसित करने में सलंग्न था। संघ के समेकन में यूएई की राजनीतिक कठिनाइयों ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी प्रारंभिक समन्वय पर एक अमिट छाप छोड़ी जो बाद में जीसीसी के सदस्य बन गए। यूएई कतर को छोड़कर सभी जीसीसी देशों के साथ गर्म संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा। जरूरत पड़ने पर इसने जीसीसी के सदस्य देशों का समर्थन किया। जब 2011 में अरब वसंत इन देशों में पहुंचा और बहरीन और ओमान जैसे देशों में विरोध प्रदर्शन हुए, तो यूएई ने प्रभावित देशों में सैन्य सैनिक और वित्तीय सहायता भेजी।

जीसीसी में तत्काल पड़ोसियों के बीच अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद, संयुक्त अरब अमीरात ने अन्य अरब देशों की ओर पहुंच बढ़ाई। यूएई सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा रहा है जिसने सना में

अब्द्राबुह मंसूर हादी सरकार को बहाल करने के लिए मार्च 2015 में यमन में हस्तक्षेप किया था। इसी तरह यूएई ने सीरियाई संकट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को आकार देने में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया ने संघर्ष के चरम के दौरान भी द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा, नियमित उड़ानों ने असद के आंतरिक सर्कल के लिए शरण की पेशकश की। संयुक्त अरब अमीरात ने सद्दाम युग के बाद बगदाद की ओर हाथ बढ़ाया और इराक के स्थिरीकरण के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, इराकी पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन मिशनों की मेजबानी की और पुनर्निर्माण गतिविधियों को वित्त पोषित किया।

अपने आर्थिक संसाधनों और अरब वसंत के दौरान इस्लामी ताकतों से खतरे की धारणा के कारण क्षेत्रीय गतिशीलता में बढ़ते कद के साथ, संयुक्त अरब अमीरात ने पड़ोस से परे अपनी पहुंच का विस्तार किया। इसने अफ्रीकी देशों में एक सक्रिय विदेश नीति का पीछा किया और 2018 में इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महत्वपूर्ण था। तालिबान के साथ यूएई का जुड़ाव इस क्षेत्र के बाहर अपनी पहुंच का विस्तार करने की अमीरात की इच्छा का एक और उदाहरण है। 11 सितंबर के हमलों के बाद, अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के लिए अपनी सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी।

क्षेत्र के भीतर और बाहर अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए, यूएई विदेश नीति के संबंध में साहसिक कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा है। पिछले दशक में संयुक्त अरब अमीरात अपने दम पर खड़ा था, कतर को अवरुद्ध करने वाली चौकड़ी का हिस्सा था, यमन संघर्ष में भागीदारी के मुद्दे पर सऊदी अरब के साथ टूट गया, यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ गठबंधन नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हथियार बिक्री पर वार्ता को रोक दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएई ने 2021 में इजरायल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

21वीं सदी में, संयुक्त अरब अमीरात ने क्षमता निर्माण के साथ-
साथ क्षमता प्रक्षेपण पर ध्यान केंद्रित किया है और यह नेता
द्वारा लिए गए विदेश नीति के निर्णयों को दर्शाता है।

21वीं सदी में, संयुक्त अरब अमीरात ने क्षमता निर्माण के साथ-साथ क्षमता प्रक्षेपण पर ध्यान केंद्रित किया है और यह नेता द्वारा लिए गए विदेश नीति के निर्णयों को दर्शाता है। संयुक्त अरब अमीरात वैश्विक मानवीय पहलों तक पहुंचने और समर्थन करने वाले पहले देशों में से एक था और नॉवल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे देशों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का 80 प्रतिशत इसकी सहायता के लिए जिम्मेदार था। यूएई अब एक प्रतिक्रियाशील बल होने से संतुष्ट नहीं है; यह विदेश नीति में सक्रिय कदम उठा रहा है। पिछले भाग में चर्चा किए गए साहसिक उपायों ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक

सक्रिय और मुखर राष्ट्र की छवि बनाई है। यह नैतिक कम्पास के माध्यम से चीजों को समझने के बजाय अपने हितों के अनुसार मुद्दों और घटनाओं का मूल्यांकन करने में आदर्शवादी प्रवृत्तियों से यथार्थवाद की ओर बढ़ रहा है। नए नेता क्षेत्रीय और वैश्विक बदलती गतिशीलता के प्रति सचेत हैं और साहसिक कदम उठाने और संबंधित जोखिम लेने के लिए तैयार हैं।

हार्ड कोर बदलावों के साथ-साथ यूएई सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर भी फोकस कर रहा है। यह सामाजिक स्तर पर बदलाव ला रहा है जिसका प्रभाव क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच ने यूएई के लिए एक उदार छवि बनाई है। वीजा नियमों और श्रम कानूनों से संबंधित सुधार भी यूएई के एक उदार और उदार चेहरे को पेश करते हैं। इसी तरह समाज के लिए एक समग्र धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण संयुक्त अरब अमीरात को एक ऐसे देश के रूप में चित्रित करता है जो अन्य धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए तैयार है। उदार संपत्ति और बुनियादी ढांचे के कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि खाड़ी देश व्यावसायिक कार्यालयों के लिए पहली प्राथमिकता के रूप में उभरता है। इसके साथ ही सरकार की सख्त आतंकवाद विरोधी नीति भी यूएई के लिए एक सकारात्मक छवि पेश करती है।

बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में यूएई सुरक्षा विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसने महसूस किया है कि यह बहु-वेक्टर साझेदारी का युग है और किसी एक वैश्विक प्रमुख शक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। पश्चिमी विकल्पों के नुकसान की भरपाई करने और अपनी विदेश नीति में विविधता लाने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात ने विशेष रूप से पूर्व और एशिया की ओर देखना शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात तकनीकी प्रगति के मामले में एक मध्य शक्ति है और एशियाई देशों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है। यूएई साझेदारी के लिए दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई देशों की ओर भी देख रहा है। यह भारत को एक बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बनाने का इरादा रखता है। अंत में, संयुक्त अरब अमीरात ने महसूस किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के सीमित लाभ हैं और त्रिपक्षीय, मिनीलेटरल और बहुपक्षीय साझेदारी भविष्य हैं। बहुध्रुवीय दुनिया में, महाद्वीपों में फैले विभिन्न विशिष्ट मुद्दों पर बहुपक्षीय साझेदारी फायदेमंद होगी। यूएई का मानना है कि मल्टी-नेटवर्क दुनिया के युग में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए खाड़ी, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने की आवश्यकता है। यूएई पड़ोस के साथ-साथ उससे परे कनेक्टिविटी के महत्व को भी समझता है।

बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए,
वर्तमान में यूएई सुरक्षा विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
इसने महसूस किया है कि यह बहु-वेक्टर साझेदारी का युग है और
किसी एक वैश्विक प्रमुख शक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहता है।

जैसा कि स्पष्ट है, एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद, संयुक्त अरब अमीरात इस क्षेत्र के भीतर और बाहर भी अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। मोहम्मद बिन जायेद के नेतृत्व में, इसका उद्देश्य अपनी विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं को साकार करना है। अपार आर्थिक संसाधन इसे आने वाले दशकों में एक सुदृढ़ और बहुमुखी विदेश नीति को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। अबू धाबी क्षेत्र में अमेरिका के घटते हितों के मद्देनजर अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति के साथ अपने संबंधों में विविधता लाने पर विचार कर रहा है। वह रूस और चीन के साथ संबंध विकसित करने से पीछे नहीं हट रहा है। इसका उद्देश्य ईरान जैसे क्षेत्रीय अछूत राज्यों के साथ भी कामकाजी संबंध विकसित करना है। एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद, शेख जायेद बिन सुल्तान का यूएई उम्र में आ गया है और मोहम्मद बिन जायेद के नेतृत्व में अपने पंखों का विस्तार कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और बढ़ती आर्थिक स्थिति के साथ, संयुक्त अरब अमीरात एक हद तक अपनी छोटीता को दूर करने में कामयाब रहा है और विदेश नीति इसे प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद उपकरण रही है।

पाद-टिप्पणियाँ

सप्रू
हाउस
पेपर

1 2015 के संघीय कानून संख्या (1) के तहत संशोधित मानव ट्रैफिकिंग अपराधों का मुकाबला करने पर 2006 का संघीय कानून संख्या (51), मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय समिति, https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af9414551-7bc4-47c5-a4ee-5d11b22ce1f2#pageNum=1 पर उपलब्ध है (4 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

2 "यूएई में घरेलू काम: दिन की नैतिक दुविधा", टीपीक्यू, 27 जून, 2019, http://turkishpolicy.com/article/963/domestic-work-in-the-uae-the-moral-dilemma-of-the-day-off#_ftnref14 पर उपलब्ध है (4 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

3 संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून, श्रम मंत्रालय, https://www.uaelaborlaw.com/ पर उपलब्ध है (4 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

4 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=ARE&p_count=203&p_classification=23&p_classcount=11 पर उपलब्ध है (7 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

5 हसन हमदान अल-अलकिम, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, 1989, साकी बुक्स, लंदन, पृष्ठ 32.

6 रमोला तलवार बादाम, "यूएई-फिलीपींस श्रम समझौता घरेलू श्रमिकों की रक्षा कैसे करेगा", द नेशनल न्यूज, 3 मार्च, 2021, https://www.thenationalnews.com/uae/government/ how-the-uae-philippines-labour-agreement-will-protect-domestic-workers-1.1176867 पर उपलब्ध है (7 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

7 शेरोक जकारिया, "संयुक्त अरब अमीरात में फिलिपिनो नौकरानियों की भर्ती अब 8,000 दिरहम तक सस्ती हो गई है", खलीज टाइम्स, 15 मई, 2018, https://www.khaleejtimes.com/uae/hiring-of-filipino-maids-in-uae-now-cheaper- by-dh8000?_refresh=true पर उपलब्ध है (7 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

8 "मैंने आपको पहले ही खरीद लिया": संयुक्त अरब अमीरात में महिला प्रवासी घरेलू श्रमिकों का दुरुपयोग और शोषण", ह्यूमन राइट्स वॉच, 22 अक्तूबर, 2014, https://www.hrw.org/report/2014/10/22/i-already-bought-you/abuse-and-exploitation-female-migrant-domestic-workers पर उपलब्ध है (7 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

9 संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी श्रमिकों की रक्षा के लिए श्रम सुधारों की घोषणा की", अल जज़ीरा, 20 सितंबर, 2015, https://www.aljazeera.com/economy/2015/9/29/uae-announces-labour-reforms-to-protect- foreign-workers पर उपलब्ध है (7 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).हसन हमदान अल-अलकिम, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, 1989, साकी बुक्स, लंदन, पृष्ठ 32.

10 अनीशा राय, राचा राया, मित्री हज्जर, स्वप्ना कोशी, संयुक्त अरब अमीरात में जनमत और एजेंडा सेटिंग: एक मात्रात्मक सामग्री विश्लेषण, 2017, पृष्ठ 273-286 पर उपलब्ध है https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1989&context=dubaipapers (7 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

11 "डेविड पोलक, कैथरीन क्लीवलैंड, यूएई पब्लिक इजरायल के साथ और कतर के साथ शांति की ओर बढ़ता है", फिकरा फोरम, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट, 10 दिसंबर, 2020, https://www.washingtoninstitute.org/ policy-analysis/uae-public-shifts-toward-peace-israel-and-qatar पर उपलब्ध है (7 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

12 दाना एल कुर्द, "यूएई में फिलिस्तीन समर्थक एकजुटता: अमीराती कार्यकर्ताओं से एक विचार", MEI@75, 2 फरवरी, 2022, https://www.mei.edu/publications/pro-palestine-solidarity-uae-view-emirati-

13 activists पर उपलब्ध है (15 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

14 जेम्स ज़ोग्बी, एलिजाबेथ ज़ोग्बी, सारा होप ज़ोग्बी, "मध्य पूर्व पब्लिक ओपिनियन, 2018", सर बानी यास फोरम, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2018/12/8a1be-2018SBYFINALWEB. pdf पर उपलब्ध है (15 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

15 "यूएई ने असद के लिए बूस्ट में सीरिया दूतावास को फिर से खोला", रॉयटर्स, 27 दिसंबर, 2018, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-emirates-idUSKCN1OQ0QV पर उपलब्ध है (18 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

16 2009 के माध्यम से संशोधन के साथ संयुक्त अरब अमीरात का 1971 का संविधान, गठन परियोजना, https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=en पर उपलब्ध है (18 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

17 हसन हमदान अल-अलकिम, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, 1989, साकी बुक्स, लंदन, पृष्ठ 32.

18 "संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति में परिवर्तन", अल जज़ीरा, 8 जून, 2017, https://studies.aljazeera.net/ar/node/1528 पर उपलब्ध है (18 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

19 दिवंगत शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान, क्राउन प्रिंस कोर्ट, https://www.cpc.gov. ae/en-us/theuae/Pages/LateSheikhZayed.aspx पर उपलब्ध है (18 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

20 करम शहरौर, "अमीराती विदेश नीति का विकास (1971-2020): असीम महत्वाकांक्षाओं के साथ एक छोटे राष्ट्र का अप्रत्याशित उदय", साइंसेज पीओ, 2020, https://www.sciencespo.fr/ kuwait-program/wp-content/uploads/2021/02/Shahrour-Karam-The-evolution-of-Emirati-foreign- policy-1971-2020.pdf पर उपलब्ध है (18 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

21 रॉबर्ट एफ वर्थ, "मोहम्मद बिन जायेद का मध्य पूर्व के भविष्य का डार्क विजन", द न्यूयॉर्क टाइम्स, 22 जनवरी, 2020, https://nyti.ms/37NmBqJ पर उपलब्ध है (7 अप्रैल, 2022 को अभिगम्य)

22 लिआ शेरवुड, "जोखिम विविधीकरण और संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति", खालिद अल्मेजैनी और जीन-मार्क रिकली (एड), द स्मॉल गल्फ स्टेट्स। अरब वसंत से पहले और बाद में विदेश और सुरक्षा नीतियां। लंदन, रूटलेज, 2017, पृष्ठ 11.

23 गुनेट, फिलिप हेनरी और स्टीफन लैक्रोइक्स (साक्षात्कार), "लेस एमिरात्साराबेस यूनिस, अन एक्ट्यूर्मेकोन्नू", ओरिएंट एक्सएक्सआई, 12 फरवरी, 2018, https://orientxxi.info/magazine/les-emirats-arabes-unis-un- acteur-meconnu,2271 पर उपलब्ध है (6 अप्रैल, 2022 को अभिगम्य).

24 आबिद हुसैन, "आर्थिक कूटनीति और विदेश नीति के लिए इसका महत्व", भारतीय विदेश मामलों के जर्नल, 2006, 1 (4), पृष्ठ 35-45.

25 इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर समन्वय पूरी कर ली है, प्रेस विज्ञप्ति, विदेश मंत्रालय, इज़राइल सरकार, 2 अप्रैल, 2022, https://www.gov.il/en/ departments/news/israel-and-the-uae-complete-negotiations-on-bilateral-free-trade-agreement-2-apr-2022 पर उपलब्ध है (7 अप्रैल, 2022 को अभिगम्य).

26 संयुक्त अरब अमीरात कंट्री ब्रीफ, विदेश मामलों और व्यापार विभाग, ऑस्ट्रेलिया सरकार, https://www.dfat.gov.au/geo/united-arab-emirates/united-arab-emirates-country-brief पर उपलब्ध है (19 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

27 संयुक्त अरब अमीरात ने 10X10 चैलेंज और यूएई डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता मंच, संयुक्त अरब अमीरात, कैबिनेट मामलों के मंत्रालय, 27 नवंबर, 2018 को लॉन्च किया, https://www.moca.gov.ae/en/media/ news/the-uae-launches-10x10-challenge-and-uae-digital-competitiveness-platform पर उपलब्ध है (19 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

28 कनिष्क सिंह, "यूएई का कहना है कि यह ओपेक+समझौते, मासिक तंत्र के लिए प्रतिबद्ध है", रॉयटर्स, 10 मार्च, 2022, https://www.reuters.com/business/energy/uae-favors-oil-production-increase-media-citing-ambassador-us-2022-03-09/ पर उपलब्ध है (19 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

29 "व्याख्याकर्ता: ओपेक तेल उत्पादन पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का झगड़ा", अल जज़ीरा, 5 जुलाई, 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/explainer-uae-saudi-arabia-spat-over-opec-oil-production पर उपलब्ध है (19 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

30 "सऊदी और यूएई ओपेक + गतिरोध में समझौता करते हैं", अल जज़ीरा, 14 जुलाई, 2021, https:// www.aljazeera.com/economy/2021/7/14/saudi-and-uae-reach-compromise-in-opec-standoff पर उपलब्ध है (19 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

31 संयुक्त अरब अमीरात में विदेशी निवेश के लिए महान विकास संभावनाएं, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात, https://www.moec.gov.ae/en/foreign-investment-inflow पर उपलब्ध है (19 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

32 जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते संयुक्त अरब अमीरात की शीर्ष वैश्विक रैंकिंग, संयुक्त अरब अमीरात, कैबिनेट मामलों के मंत्रालय का समर्थन करते हैं। https://www.moec.gov.ae/en/web/guest/-free-trade-agreements, (19 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

33 रोरी जोन्स और डोव लिबर, "यू.ए.ई. इजरायल के टेक सेक्टर में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया क्योंकि दोनों देश करीब आ रहे हैं", द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 14 जनवरी, 2022, https://www.wsj.com/articles/u-a-e- sovereign-wealth-fund-invests-100-million-in-israel-venture-capital-firms-11642164356 पर उपलब्ध है (19 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

34 "संयुक्त अरब अमीरात जिम्बाब्वे व्यापार के साथ अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाना जारी रखता है", अल मॉनिटर, 19 मार्च, 2022, https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/uae-continues-grow-influence-africa-zimbabwe-trade#:~:text=Why%20it%20matters%3A%20The%20UAE,over%20the%20next%20few%20years पर उपलब्ध है (10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

35 "जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात ने टेक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन निवेश कोष लॉन्च किया", गैजेट्स

नाउ, 9 जून, 2022, https://www.gadgetsnow.com/tech-news/jordan-uae-launch-100-million- investment-fund-to-boost-tech-cooperation/articleshow/92105435.cms#:~:text=Jordan%20and%20
36 the%20United%20Arab,Wednesday%2C%20Xinhua%20news%20agency%20reported पर उपलब्ध है (10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
37 श्वेता जैन, "यूएई ने निवेश की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए इराक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए", द नेशनल न्यूज, 19 अक्तूबर, 2021, https://www.thenationalnews.com/business/2021/10/19/uae-signs-deal-
38 with-iraq-to-protect-and-promote-investments/ पर उपलब्ध है (10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

39 नाडा एल सावी, "यूएई लेबनान के कुल एफडीआई का 11% योगदान देता है, राजनयिक कहते हैं", द नेशनल न्यूज, 7 अक्तूबर, 2019, https://www.thenationalnews.com/business/economy/uae-contributes-
40 11-of-lebanon-s-total-fdi-diplomat-says-1.919479 पर उपलब्ध है (10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
41 "यूएई निवेशक सीरिया में परियोजनाओं को संबंधों के रूप में तौलते हैं: अल-वतन", ब्लूमबर्ग, 13 अप्रैल, 2022, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-13/uae-investors-weigh-projects-in-syria-as-ties- warm-al-watan पर उपलब्ध है (10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
42 जमाल सनद अल सुवैदी, इक्कीसवीं सदी में संयुक्त अरब अमीरात सोसायटी: एक बदलती दुनिया में मुद्दे और चुनौतियां, 2018, यूएई सोसाइटी, पृष्ठ 83-85.
43 जोनाथन फुल्टन, "संयुक्त अरब अमीरात की धुरी एशिया के लिए", एशिया सोसाइटी, 21 सितंबर, 2020, https://asiasociety.org/asias-new-pivot/united-arab-emirates पर उपलब्ध है (10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
44 "दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात विलवणीकरण संयंत्र विकास पर संयुक्त अध्ययन पर सहमत", कोरिया टाइम्स, 31 मई, 2016, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/11/113_205921.html पर उपलब्ध है (10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
45 दानिया सादी, "संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल जल विलवणीकरण, सौर ऊर्जा पर सहयोग कर सकते हैं: मंत्री", एसपीजी ग्लोबल, 15 सितंबर, 2020, https://www.spglobal.com/commodityinsights/ko/market-insights/ latest-news/electric-power/091520-uae-israel-may-cooperate-on-water-desalination-solar-energy- minister पर उपलब्ध है (15 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
46 शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान, द लीडर एंड द नेशन, द अमीरात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च, 2004, पृष्ठ 219-222.
47 जेफ अब्रामसन, "यू.एस. अभी भी प्रमुख यूएई हथियार बिक्री की तलाश है", आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन, मई 2021, https://www.armscontrol.org/act/2021-05/news/us-still-seeks-major-uae-arms-sale पर उपलब्ध है (15 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
48 "संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमेरिकी सुरक्षा सहयोग", अमेरिकी विदेश विभाग, 25 जून, 2021, https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-the-united-arab-emirates/ पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
49 "भारत यूएई द्विपक्षीय रक्षा सहयोग", भारतीय दूतावास, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, https://www.indembassyuae.gov.in/defence-relation.php#:~:text=Bilateral%20Defence%20 Interaction%20between%20India,education%20exchanges%20between%20the%20countries पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
50 "तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात ने रक्षा उद्योग सहयोग के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए", डेली सबा, 30 मई, 2022, https://www.dailysabah.com/business/defense/turkey-uae-ink-2-mous-for-defense-industry-cooperation पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).
51 फ्राउके हर्ड-बे, ट्रुशियल स्टेट्स से यूएई तक: ए सोसाइटी इन ट्रांजिशन, लॉन्गमैन, लंदन, न्यूयॉर्क, पृष्ठ 381.
52 शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान, द लीडर एंड द नेशन, द अमीरात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च, 2004, पृष्ठ 241-242.
53 एडम क्रिज़िमोव्स्की, "अपनी सॉफ्ट पावर रणनीति और सतत विकास लक्ष्यों के लिए संयुक्त अरब अमीरात विदेशी सहायता की भूमिका और महत्व", सामाजिक विज्ञान, एमडीपीआई, 11 (48), पृष्ठ 1-18.
54 हसन हमदान अल-अलकिम, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, 1989, साकी बुक्स, लंदन, पृष्ठ 59.
55 एमईजे, वॉल्यूम XXVII, संख्या 3, 1973, हसन हमदान अल-अलकिम में पृष्ठ 367, 1989, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, साकी बुक्स, लंदन, पृष्ठ 59.
56 लक्ष्मी प्रिया, "संयुक्त अरब अमीरात पर हूथी ड्रोन और मिसाइल हमलों के निहितार्थ", भारतीय वैश्विक परिषद, 11

फरवरी, 2022, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_ id=7043&lid=4783 पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

57 लक्ष्मी प्रिया, "हूती हमलों के मद्देनजर यूएई की सुरक्षा पर पुनर्विचार", रक्षा अनिरवेदा, 6 फरवरी, 2022, https://raksha-anirveda.com/rethinking-uaes-security-in-the-wake-of-houthi-

58 attacks/ पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

59 विदेश नीति, संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास, वाशिंगटन डीसी, https://www. uae-embassy.org/discover-uae/foreign-policy पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

60 एम एस अगवानी, गल्फ में राजनीति, 1978, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ 124-25.

61 ब्रायन रौप, बालासुंदरम मनियम, सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी, "वैश्विक महाशक्ति की स्थिति की दौड़: क्या अमेरिका अपनी पकड़ खो रहा है?". इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 7 (4.28), नवंबर 2018, पृष्ठ 1509-1515।

62 माइकल कॉक्स, "पावर शिफ्ट्स, इकोनॉमिक चेंज एंड द डिपोजिट ऑफ द वेस्ट?", केनेथ एन वाल्ट्ज व्याख्यान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सेज प्रकाशन, 26 (4), 2012, पृष्ठ 369-388.

63 इब्राहिम करातास, "संयुक्त राष्ट्र अमेरिका: क्या यह अभी भी एक महाशक्ति है?", सुलेमान डेमिरेल यूनिवर्सिटी विजनरी जर्नल, 12 (30), 2021, 677-688.

64 सैमुअल रमानी, "रूस और संयुक्त अरब अमीरात: एक वैचारिक साझेदारी", मध्य पूर्व नीति, 27 (1), 2020, पृष्ठ 125-140.

65 अकरम उमारोव, "रूस और संयुक्त अरब अमीरात: द्विपक्षीय सहयोग में आतंकवाद का मुकाबला करने की भूमिका", कट्टरता पर यूरोपीय आंख, 13 दिसंबर, 2019, https://www.academia.edu/45094882/ Russia_and_UAE_The_Role_of_Counterterrorism_in_Bilateral_Cooperation पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

66 मोहम्मद बिन हुवैदीन, "संयुक्त अरब अमीरात के साथ चीन की सामरिक साझेदारी: नींव और संभावनाएं", तुलनात्मक रणनीति, 2022, https://www.researchgate.net/publication/359993115 पर उपलब्ध है China's_Strategic_Partnership_with_the_UAE_Foundation_and_Prospects (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

67 जीसीसी आर्थिक एकीकरण: एक सुदृढ़ और एकीकृत जीसीसी के लिए, वित्त मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात, https://www.mof.gov.ae/en/StrategicPartnerships/Pages/GCCEconomicIntegration.aspx पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

68 हसन हमदान अल-अलकिम, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, साकी पुस्तकें, लंदन, 1989, पृष्ठ 118.

69 मेट्ज़, फारस की खाड़ी के राष्ट्र: देश के अध्ययन, संघीय अनुसंधान प्रभाग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन डीसी, 1994.

70 बहरीन: अमेरिकी नीति के लिए मुद्दे, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, 10 मार्च, 2022, https://sgp. fas.org/crs/mideast/95-1013.pdf पर उपलब्ध है (25 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

71 कतर: शासन, सुरक्षा और अमेरिकी नीति, कांग्रेस अनुसंधान सेवा, 11 अप्रैल, 2022, https://sgp.fas.org/crs/mideast/R44533.pdf पर उपलब्ध है (27 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

72 ओमान: राजनीति, सुरक्षा और अमेरिकी नीति, कांग्रेस अनुसंधान सेवा, 1 जून, 2022, https://sgp.fas.org/crs/mideast/RS21534.pdf पर उपलब्ध है (23 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

73 "ओमान का कहना है कि यह यूएई-इजरायल संबंधों के सामान्यीकरण का समर्थन करता है", अल मॉनिटर, 14 अगस्त, 2020, https://www.al-monitor.com/originals/2020/08/oman-israel-uae-agreement-normalize-ties-trump-us-deal.html पर उपलब्ध है (23 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

74 अब्दुल वहाब अल-क़साब, "यमन में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका के सामरिक विचार", अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी, 9 मार्च, 2018, https://arabcenterdc.org/resource/strategic- considerations-of-the-uaes-role-in-yemen/ पर उपलब्ध है (01 फ़रवरी, 2022 को अभिगम्य).

75 अरवा मोकदाद, "यमन के द्वीपों के संयुक्त अरब अमीरात के अधिग्रहण का वास्तव में क्या मतलब है", जिम्मेदार स्टेटक्राफ्ट, 14 जून, 2021, https://responsiblestatecraft.org/2021/06/14/what-the-uae-takeover-of-yemens-islands-really-means/ पर उपलब्ध है (01 फ़रवरी, 2022 को अभिगम्य).

76 नासिर अल वासमी, आर्थर मैकमिलन, "डॉ अनवर गर्गश: कतर संकट को हल करने में 'विश्वास घाटे' से निपटना शामिल होना चाहिए", द नेशनल न्यूज, 7 जून, 2018, https://www.thenationalnews. com/world/mena/dr-anwar-gargash-solving-the-qatar-crisis-must-involve-tackling-the-trust-deficit-1.737701 पर उपलब्ध है (01 फ़रवरी, 2022 को अभिगम्य).

77 संयुक्त अरब अमीरात (यूएई): अमेरिकी नीति के लिए मुद्दे, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, 10 मई, 2022, https://sgp.fas.org/crs/mideast/RS21852.pdf पर उपलब्ध है (27 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

78 पूर्वोक्त

79 "अफ्रीका के हॉर्न में संयुक्त अरब अमीरात", ब्रीफिंग नंबर 65, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-arab- emirates/b65-united-arab-emirates-horn-africa पर उपलब्ध है (27 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

80 संयुक्त अरब अमीरात (यूएई): अमेरिकी नीति के लिए मुद्दे, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, 10 मई, 2022, https://sgp.fas.org/crs/mideast/RS21852.pdf पर उपलब्ध है (26 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

81 "सऊदी-यूएई विभाजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि दुनिया हरी नहीं हो जाती है", लाइव मिंट, 25 जुलाई, 2021, https:// www.livemint.com/news/world/saudiuae-split-won-t-end-until-the-world-goes-green-11627194013102. html पर उपलब्ध है (20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

82 "सऊदी और यूएई ओपेक+गतिरोध में समझौता करते हैं", अल जज़ीरा, 14 जुलाई, 2021, https:// www.aljazeera.com/economy/2021/7/14/saudi-and-uae-reach-compromise-in-opec-standoff पर उपलब्ध है (27 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

83 हसन हमदान अल-अलकिम, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, साकी किताबें, लंदन, 1989, पृष्ठ 137-170.

84 यूएई, ईरान ने संभावित राजदूत की वापसी से पहले संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की", द हिंदू, 27 जुलाई, 2022, https://www.thehindu.com/news/international/uae-iran-discuss-boosting-ties-ahead- of-possible-ambassador-return/article65690873.ece पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

85 गॉर्डन लुबोल, वॉरेन पी स्ट्रोबेल, "संयुक्त अरब अमीरात ने 23 बिलियन डॉलर के एफ -35, अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे से बाहर निकलने की धमकी दी है", द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 14 दिसंबर, 2021, https://www.wsj.com/articles/ united-arab-emirates-threatens-to-pull-out-of-23-billion-f-35-drone-deal-with-u-s-11639491997 पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

86 "संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी राज्यों के 'सैन्य' साइट के उपयोग के बाद चीन सुविधा को बंद कर दिया", लाइव मिंट, 12 दिसंबर, 2021, https://www.livemint.com/news/world/uae-shuts-down-china-facility-after-us-states-military-use-of-site-11639289301925.html पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

87 डैन मर्फी, "यूएई ने चीन के साथ एक विशाल, $ 3.4 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए-और यह 'आश्चर्य की बात नहीं है,"सीएनबीसी न्यूज, 29 अप्रैल, 2019 https://finance.yahoo.com/news/uae-signed-massive-3-4-050538220. html पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

88 नी जियान, "यूएई के साथ चीन के संबंध भाईचारे के समान क्यों हैं", संयुक्त अरब अमीरात में चीनी राजदूत ने द नेशनल न्यूज में लिखा, https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/why-china- s-relationship-with-the-uae-is-brotherly-1.868032 पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

89 चीन, संयुक्त अरब अमीरात व्यापक सामरिक साझेदारी के संबंधों को बढ़ाने के लिए सहमत हुए, चीन के विदेश मंत्रालय, 20 जुलाई, 2022 को https://www.mfa.gov.cn/ce/como/eng/news/t1579379.htm पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

90 हसन हमदान अल-अलकिम, संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति, साकी पुस्तकें, लंदन, 1989, पृष्ठ 171-206.

91 "सीक्रेट एलायंस: इजरायल ने मिस्र में हवाई हमले किए, काहिरा के ओके के साथ", न्यूयॉर्क टाइम्स। 3 फरवरी, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai- egypt.html पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

92 "रिपोर्ट: इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात यमन में जासूसी ठिकानों की स्थापना", इज़राइल हायोम, 31 अगस्त, 2020, https://www.israelhayom.com/2020/08/31/report-israel-uae-setting-up-spy-bases-in-yemen/ पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

93 अब्राहम समझौता शांति समझौता: संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल राष्ट्र के बीच शांति, राजनयिक संबंधों और पूर्ण सामान्यीकरण की संधि, https://www.state.gov/

94 wp-content/uploads/2020/09/UAE_Israel-treaty-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

95 "समझौतों का भविष्य", अब्राहम एकॉर्ड्स पीस इंस्टीट्यूट, https://www.aapeaceinstitute. org/impact पर उपलब्ध है (30 जुलाई, 2022 को अभिगम्य).

96 ब्रूस डब्ल्यू जेनटलसन, अमेरिकी विदेश नीति, 21वीं सदी में पसंद की गतिशीलता, ए डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन एंड कंपनी स्टडी

स्पेस।

97 संयुक्त अरब अमीरात के सूचना और संस्कृति मंत्रालय, मजमूत तसरीहा हदीस वा तसरीहत साहिब अल सूमू अल शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान (अबू धाबी: एनडी), संयुक्त शक्ति के साथ 30-31: एच एच शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान, द लीडर एंड द नेशन, द अमीरात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च, 2004, पृष्ठ 219.

98 अलमेजैनी, संयुक्त अरब अमीरात और विदेश नीति, विदेशी सहायता, पहचान और हित, रूटलेज, 2014, पृष्ठ 106.

99 अल-सखनी, अहमद अली, शेख जायेद: फलसफातो होकम वैनबीटो उम्माह। (शेख जायेद: शासन का दर्शन और एक राष्ट्र का पुनर्जागरण), अल राद वैज्ञानिक पुस्तकालय, अम्मान, 1998.

100 सीबीयूएई, संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक में क्षमता निर्माण, यहाँ उपलब्ध है https://www.sesric.org/imgs/news/ image/483-p7-UAE-CAPACITY-BUILDING.pdf (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

101 अबू धाबी इकोनॉमिक विजन 2030, यूएई कहाँ उपलब्ध है https://u.ae/en/about-the-uae/strategies- initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/abu-dhabi-economic-vision-2030#:~:text=Entitled%20'Abu%20Dhabi%20Economic%20Vision,is%20responsive%20to%20 economic%20cycles(30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य)

102 कोविड-19 के दौरान यूएई के मानवीय प्रयास, यूएई, यहां उपलब्ध हैं https://u.ae/en/information- and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/humanitarian-efforts#:~:text=The%20UAE's%20global%20efforts%20to%20combat%20the%20COVID%2D19%20 outbreak,-The%20UAE%20was&text=As%20of%20July%202021%2C%20the,medical%20aid%20 flights%20were%20sent. (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

103 संयुक्त अरब अमीरात अर्थव्यवस्था, संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास, वाशिंगटन डीसी, https://www.uae-embassy.org/ business-trade/uae-economy पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

104 इवा हमेल्घरम अल्कास्टेलानी डेक्सटर, "यूएई: द स्काई लिंग सुधार की सीमा है", विश्व बैंक, 10 मार्च, 2021, https://blogs.worldbank.org/arabvoices/gender-reforms-united-arab-emirates पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

105 सकीना फातिमा ने कहा, "दुबई का नया हिंदू मंदिर अक्तूबर में खुलने के लिए पूरी तरह तैयार है; विवरण जानें", द सियासत डेली, 10 अगस्त, 2022, https://www.siasat.com/dubais-new-hindu-temple-is-all-set-to- open-in-october-know-details-2387156/ पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

106 "दुबई में विदेशी निवेश से संबंधित कानून", कॉर्पोरेट समूह, दुबई, उपलब्ध https://companyincorporationdubai.com/legislation-related-to-foreign-investments-in-dubai/ (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

107 आतंकवाद और अतिवाद का मुकाबला करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, https://www.mofaic.gov.ae/en/the-ministry/the-foreign-policy/combating-terrorism-and- extremism पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

108 मंत्रिमंडल ने उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी, 08 जून, 2022, पत्र सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, https://pib.gov.in/PressReleasePage.

109 aspx?PRID=1832176#:~:text=The%20Union%20Cabinet%20chaired%20by,of%20Industries%20and%20 Advanced%20Technologies. पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

110 "अबू धाबी उद्योग पर चीनी प्रांत के साथ सहयोग करने के लिए", अल मॉनिटर, 10 जून, 2022, https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/abu-dhabi-cooperate-chinese-province-industry पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

111 रुफ माम्मादोव, "संयुक्त अरब अमीरात मध्य एशिया में खाड़ी आउटरीच का नेतृत्व करता है", मध्य पूर्व संस्थान, 03 अप्रैल, 2019, https://www.mei.edu/publications/uae-leads-gulf-outreach-central-asia पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

112 "खाड़ी देश और मध्य एशिया साझेदारी का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं", समाचार मध्य एशिया, 08 सितंबर, 2022 newscentralasia.net/2022/09/08/gulf-countries-and-central-asia-are-eager-to पर उपलब्ध है-विस्तार-साझेदारी/(30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य)।

113 "फार्म-टू-पोर्ट: यूएई को खिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की विशेष परियोजना", फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 06 मार्च, 2017, https://www.financialexpress.com/india-news/farm-to-port-pm-narendra-modis-special- project-to-feed-

uae/576703/ पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

114 "एतिहाद रेल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)", रेलवे प्रौद्योगिकी, 08 सितंबर, 2022, https://www.railway-technology.com/projects/etihad-rail/ पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

115 "मुंबई से फुजैरा 2 घंटे में! यूएई ने भारत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पानी के नीचे बुलेट ट्रेन की योजना बनाई है", बिजनेस टुडे, 05 दिसंबर, 2018, https://www.businesstoday.in/latest/

116 economy-politics/story/mumbai-to-fujairah-in-2-hours-uae-plans-underwater-bullet-train-to-boost-connectivity-with-india-119401-2018-12-05 पर उपलब्ध है (30 सितंबर, 2022 को अभिगम्य).

सप्रू हाउस पेपर

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001, भारत,
टेलीफोन: +91-11-2331 7242, फैक्स: +91-11-2332 2710

www.icwa.in